

● वर्ष-6
● अंक-74
रायपुर, शनिवार 24 अक्टूबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-३ रु.

॥ संगछध्वम् संवदध्वम् ॥

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>>
मैनपाट टाइटन्स-बैलाडिला बुल्स...

आदिवासी समाज की परंपरागत व्यवस्था सामाजिक एकता, न्याय और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण : राष्ट्रपति मुर्मू

चुनौतियों का सामना करने समाज एकजुट हो एक दिन में नौ स्वर्ण

जगदलपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार में आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक निर्णय प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की परंपरागत व्यवस्था सामाजिक एकता, न्याय, आपसी सहयोग और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि समय के साथ शासन व्यवस्था, नीतियां और कानून बदलते रहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं, सामाजिक नियमों और अलिखित संविधान को पीढ़ियों से जीवित रखा है। यह व्यवस्था समाज में सुख-शांति, प्रेम, सद्भाव और सामूहिकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण आधार है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने मुरिया दरबार में उपस्थित आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और पारंपरिक प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने मुझे एक बार फिर अपनी संस्कृति और परंपराओं से रूबरू होने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी आदिवासी संस्कृति और परंपरा से आती हूँ। मेरे दादाजी



मांझी थे, मेरे पिताजी भी मांझी थे और मेरे भाई भी मांझी हुआ करते थे। मैं एक मांझी की बेटी हूँ, गांव के मुखिया की बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य आज भले ही उनके बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं के प्रति उनका जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश में पहले राजाओं का शासन था, इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया और आज भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। समय के साथ शासन व्यवस्था और कानूनों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आदिवासी समाज की अपनी पारंपरिक व्यवस्था आज भी विद्यमान है जो

किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है, लेकिन समाज के लोग पीढ़ियों से इसका पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में लोग मिल-जुलकर पूजा-अर्चना करते हैं, विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा सामूहिक रूप से पर्व-त्यौहार मनाते हैं। नृत्य, गीत-संगीत और सामूहिक उत्सवों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। उन्होंने इस समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के लिए समाज के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृति, परंपरा, संविधान और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में सुख-शांति, आनंद और प्रेम बनाए रखना है।

बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने आदिवासी समाज से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ समाज को आगे बढ़ना आवश्यक है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, उन्हें पढ़ने-लिखने और जीवन में प्रगति करने का अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि समय के साथ सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना और विकास के नए अवसरों को अपनाना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक पहचान को त्यागना नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास और सांस्कृतिक संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक शिक्षा, नई सोच और विकास के अवसरों को अपनाने हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत, रीति-रिवाजों और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी जड़ों से जुड़े रहने, पारंपरिक संस्थाओं का सम्मान करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से परिचित कराने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के विकास और कल्याण के लिए सहयोग कर रही है तथा आगे भी करती रहेगी।

मुरिया दरबार की परंपरा को जीवित रखने का किया आह्वान

राष्ट्रपति ने मुरिया दरबार जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक मूल्यों से होती है। चाहे इन परंपराओं का उल्लेख सरकारी अभिलेखों में हो अथवा न हो, समाज के लोगों को अपनी सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की परंपरागत व्यवस्था में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, सामाजिक न्याय और सुशासन की भावना निहित है। इन मूल्यों को बनाए रखना वर्तमान और भावी पीढ़ियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने बस्तर के आदिवासी समाज से मिले स्नेह, सम्मान और आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है।

देश में 2900 किलोमीटर लंबाई के दिल्ली में सशस्त्र बल की तैनाती 31 तक नमो भारत कॉरिडोर बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों के बीच तेज और बेहतर रेल संपर्क बढ़ाने के लिए करीब 2900 किलोमीटर लंबाई के संभावित नमो भारत कॉरिडोर की पहचान की गई है। इन मार्गों के विकसित होने से बड़े शहरों और आपसपास के क्षेत्रों के बीच सफर आसान हो सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से इस योजना और नमो भारत की उपलब्धियों की जानकारी दी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।



एनसीआरटीसी के अनुसार, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अक्टूबर 2023 में परिचालन शुरू होने के बाद से अब तक 4.5 करोड़ से अधिक यात्री यात्राएं दर्ज की जा चुकी हैं। इस मार्ग पर रोजाना एक लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। इस सफलता को देखते हुए देश के दूसरे क्षेत्रों में भी नमो भारत जैसी रेल सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। 23 और 24

अक्टूबर को आयोजित सम्मेलन में एनसीआरटीसी ने नमो भारत की सुविधाओं, आधुनिक तकनीक और क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था में आए बदलावों को प्रदर्शित किया।

प्रदर्शनी में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर की जानकारी भी दी गई। यह कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है और इस पर 15 स्टेशन हैं। इसी बुनियादी ढांचे पर मेरठ मेट्रो सेवा भी जोड़ी गई है, जिससे क्षेत्रीय रेल और शहर के भीतर की मेट्रो सेवा के बीच बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने अतिथियों को नमो भारत की सुविधाओं और परियोजना से यात्रियों को मिल रहे लाभों के बारे में बताया।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 273 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कंपनियों की तैनाती को दूसरी बार 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके पीछे राजनीतिक और अन्य समूहों द्वारा अचानक विरोध-प्रदर्शन (फ्लैश प्रोटेस्ट) किए जाने की आशंका का हवाला दिया गया है। कांक्रोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए, इन बलों को इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी लाया गया था। गृह मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस और संबंधित सीएपीएफ को इस तैनाती के लिए आपसी समन्वय बनाने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर इस विस्तार को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने शहर भर की कई संवेदनशील जगहों पर अचानक विरोध-प्रदर्शन होने की संभावना का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अक्टूबर के मध्य में भी इसी तरह के विस्तार को मंजूरी दी थी। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को बताया कि राजनीतिक और अन्य संगठनों द्वारा अचानक विरोध-प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनाती जारी रखना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस के साथ तैनात रहने



वाली 273 कंपनियों में से 125 कंपनियां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हैं, जिनमें महिलाओं की 20 यूनिटें शामिल हैं; 46 कंपनियां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हैं; 39 कंपनियां इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की हैं; 31 कंपनियां सशस्त्र सीमा बल की हैं; 20 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स की हैं; और 12 कंपनियां सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की हैं। सीएपीएफ की एक कंपनी में 100 कर्मियों की स्वीकृत संख्या होती है, हालाँकि इसकी वास्तविक कार्यात्मक संख्या लगभग 70-72 कर्मियों की होती है। 9 अक्टूबर को दिल्ली के कुछ हिस्सों में सीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी, मतदाता सूची केविशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

खड़गे ने भारत की चीन नीति पर स्पष्टता देने की मांग की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की चीन नीति पर स्पष्टता देने की मांग की है। उन्होंने सीमा सुरक्षा, आर्थिक संबंधों और राजनयिक मामलों को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना की है। एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, खड़गे ने प्रधानमंत्री से तीन खास सवाल पूछे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और राजनयिक जवाबदेही से जुड़े हैं। उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक के उस बयान का जिक्र किया, जिससे पुष्टि होती है कि अरुणाचल प्रदेश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ आतना-सामना चल रहा है। खरगे ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पीएलए के साथ लगातार हो रहे टकराव की आईटीबीपी के डीजी द्वारा पुष्टि, बेहद चिंताजनक है। डोकलाम और गलवान के बाद, क्या एक और गंभीर टकराव की स्थिति बन रही है? अगस्त में तक्सिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आई थीं। फिर भी, वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बाद भी – जो कि कथित तौर पर यहाँ से केवल 180 किमी दूर है।

‘स्पेडेक्स’ मिशन मिशन पूरा, दोनों सैटेलाइट सुरक्षित लौटे

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को कहा कि ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट’ (स्पेडेक्स) का हिस्सा रहे दो उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ गए हैं, जिससे लगभग 22 महीने बाद इस मिशन का समापन हो गया है। तीस दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किए गए ‘स्पेडेक्स’ मिशन के तहत दो उपग्रहों- ‘स्पेडेक्स-ए’ और ‘स्पेडेक्स-बी’ का उपयोग करके, महत्वपूर्ण स्वायत्त अंतरिक्ष मिलान और किफायती ‘डॉकिंग’ (उपग्रहों के आपस में एक-दूसरे से जुड़ने) प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। इसरो के अनुसार, ‘स्पेडेक्स-ए’ ने 12 अक्टूबर को रात 10ः18 बजे दक्षिण प्रशांत महासागर के ऊपर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया, जबकि ‘स्पेडेक्स-बी’ ने 13 अक्टूबर को सुबह 5ः06 बजे उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया। एजेंसी ने बताया कि दोनों अंतरिक्ष यानों ने अपने सभी मुख्य मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा, “परिचालन के बाद के चरण में, दोनों उपग्रहों का ईंधन खत्म हो गया; वे कक्षाओं में धीरे-धीरे नीचे आते गए।

राहुल के समर्थन में उतरे शशि थरूर, पीएम पर पलटवार

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में लोगों, खासकर युवा मतदाताओं में नया उत्साह जगाया है।



उन्होंने कहा कि अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बात पर ध्यान देने का समय आ गया है कि लोग उससे क्यों दूर हो रहे हैं। शशि थरूर ने आगे दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने इस पर ध्यान देना शुरू भी कर दिया है। यही वजह है कि वह राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर ने एक समाचार चैनल के समिट में देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए ये बातें कहीं। थरूर ने राहुल गांधी का समर्थन ऐसे समय किया है, जब हाल ही में भाजपा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें फेल प्रोडक्ट यानी असफल उत्पाद कहा। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक समाचार चैनल के समिट में बिना नाम लिए गांधी परिवार के वंशज राहुल गांधी पर निशाना साधा था।

एसआईआर पर बैठक से टीवीके-डीएमके का वॉकआउट

चेन्नई। तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्तारूढ़ टीवीके और मुख्य विपक्षी दल डीएमके समेत कई दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। इन दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए और चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बनाए नहीं रखी। हालांकि, अनाद्रमुक और भाजपा के प्रतिनिधि बैठक में शामिल रहे। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी एसएसआर पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें कई राजनीतिक दलों ने पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। विरोध करने वाले दलों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इन दलों ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट : अदालत ने नेहा बोरा की याचिका की खारिज

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने नेहा की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 130 के तहत शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में एक सभा में शामिल होने के दौरान हिरासत में लिया गया था। उनका आरोप है कि उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाकर आरके पुरम थाने में रातभर रखा गया और अगले दिन सुबह छह बजे रिहा किया गया। नोटिस में मंडी हाउस पर नारेबाजी, निषेधाज्ञा के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास विरोध प्रदर्शन और कानून अंतर्गत प्लेस के नरेश के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। नेहा बोरा ने याचिका में कहा है कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में कोई ठोस कारण, विशिष्ट घटना या समयवधि नहीं बताई गई है।

गश्त के तय तरीकों से हटती है चीनी सेना : सीमा मुद्दे पर भारत की दो टूक

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। यह बयान आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के उस कथित बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना (पीएलए) के साथ लगातार आमने-सामने की स्थिति का जिक्र किया था। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जहां तक इस मामले की खास जानकारी का सवाल है, मैं आपको रक्षा मंत्रालय से संपर्क करने के लिए कहूंगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति समय-समय पर

तब बिगड़ती है, जब चीनी सेनाएं गश्त के तय तरीकों का पालन नहीं करती हैं। उन्होंने आगे कहा, दोनों देश लंबित मुद्दों को सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गलतफहमी व गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य व्यवस्थाओं का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। दोनों देश सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त तरीकों में एलएसी की समझ बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के आपसी संबंधों के समग्र विकास के लिए जरूरी है। आईटीबीपी के

महानिदेशक के कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में खुलकर जवाब देना चाहिए।

खरगे ने कई सवाल उठाते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश में पीएलए के साथ लगातार आमने-सामने की स्थिति कि आईटीबीपी महानिदेशक की पुष्टि बेहद चिंताजनक है। डोकलाम और गलवान के बाद क्या एक और गंभीर टकराव हो रहा है? अगस्त में ताकसिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आई थीं।



इसके बावजूद, वाचा-दामाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बाद भी टकराव जारी है। बताया जा रहा है कि यह जगह ताकसिंग से केवल 180 किलोमीटर दूर है। क्या भारत की गश्त करने की पहुंच प्रभावित हुई है?

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर संसद में बयान देने को कहा। खरगे ने कहा, मोदी और (चीन के राष्ट्रपति) शी जिनपिंग के बीच कम से कम 23 बैठकें और बातचीत होने की खबरें हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सू की भागीदारी के साथ विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर 25 दौर की बातचीत हुई है। कार्यकारी तंत्र और समन्वय परामर्श (डब्ल्यूएमसीसी) की 36 बैठकें हुई हैं। इसके अलावा, शंघाई सहयोग संगठन

(एससीओ) और ब्रिक्स के लगातार शिखर सम्मेलन भी हुए हैं। इन सभी बैठकों और बातचीत से ठोस नतीजे क्या निकले हैं? उन्होंने पूछा, क्या मई 2020 से पहले भारत को गश्त करने के जो अधिकार हासिल थे, वे पूरी तरह बहाल कर दिए गए हैं? हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जवाबदेही जरूरी है, न कि कूटनीतिक तस्वीरें खिंचवाने और गले मिलने की कूटनीति! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष पर हमला करने के बजाय संसद और देश को विश्वास में लेना चाहिए।

इस साल 25 अगस्त को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की बातचीत का 25वां दौर बीजिंग में हुआ था। दोनों देशों ने इस बात को दोहराया कि वे अपने-अपने नेताओं से मिले दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा आपसी संबंधों के स्वस्थ और लगातार विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई।विदेश मंत्री एस जयशंकर की अजरबैजान यात्रा पर जायसवाल ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे विदेश मंत्री बाकू दौरे पर हैं। वह इस समय वहीं हैं।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने की मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना



अपने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति ने मां दंतेश्वरी से देशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल रमेल डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी मां दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-शान्ति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति अंचल के लोगों की अटूट श्रद्धा है। मां दंतेश्वरी बस्तर की आस्था और लोकजीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मां दंतेश्वरी के दर्शन-पूजन के लिए आगमन बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का अवसर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अपनी अनुपम जनजातीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और विशिष्ट जीवन मूल्यों के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है। यहां की परंपराओं में प्रकृति, आस्था और समाज के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। राष्ट्रपति के प्रवास से बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और सम्मान मिलेगा। बता दें कि मां दंतेश्वरी बस्तर अंचल की आराध्य देवी हैं। मां दंतेश्वरी के प्रति बस्तरवासियों की गहरी आस्था है और उनकी उपासना क्षेत्र की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा में विशेष स्थान रखती है। मां दंतेश्वरी से जुड़ी आस्था बस्तर की सदियों पुरानी परंपराओं और यहां के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में गहराई से रची-बसी है।

खाद्य विभाग का सर्वर सुचारु, राशनकार्ड से जुड़े कार्यों का नियमित संचालन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकों को खाद्य विभाग से संबंधित सेवाएं सुचारु रूप से उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर जिले में खाद्य विभाग का सर्वर सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। राशनकार्ड से संबंधित सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वर डाउन होने के कारण आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य बाधित होने जैसी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें। जिला खाद्य नियंत्रक, रायपुर ने स्पष्ट किया है कि खाद्य विभाग का सर्वर सामान्य रूप से कार्यरत है और राशनकार्ड से संबंधित कार्यों का संचालन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जा रहा है। सर्वर की तकनीकी समस्या के कारण आयुष्मान कार्ड बनाने में व्यवधान होने संबंधी जानकारी भ्रामक है। खाद्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे विभागीय सेवाओं के संबंध में अप्रुष्ट जानकारीयों से भ्रमित न हों। विभाग ने कहा है कि नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध कराना और सेवाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।

हेल्पलाइन की त्वरित पहल से सुरेश की बेटी को मिला जन्म प्रमाण पत्र



सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला तहसील अंतर्गत ग्राम बाथ निवासी श्री सुरेश कुमार सारथी की यह कहानी है, जिनकी वर्षों की चिंता एक फोन कॉल से दूर हो गई। सुरेश कुमार सारथी अपनी नवजात पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी समय से परेशान थे। आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जब उन्हें कोई अन्य रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने शासन की जन-कल्याणकारी सेवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का सहारा लिया और अपनी समस्या दर्ज कराई। हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होते ही प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। विभाग की तत्परता का यह परिणाम रहा कि कुछ ही समय में स्वास्थ्य केंद्र देवागांव द्वारा उनकी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें सौंप दिया गया।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग, दीपावली से पूर्व दें 2% महंगाई भता

रायपुर। राज्य सरकार से दीपावली से पूर्व कर्मचारियों-पेंशनरों को 2% महंगाई भता प्ररियर सहित देने की मांग की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखा है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि शीघ्र निर्णय नहीं होने पर मंत्रालय घेराव की चेतावनी दी है। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भता मिल रहा है। आईएमजे केंद्र सरकार की दर से 2 प्रतिशत कम है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

कांग्रेस ने जनजातीय समाज को बनाया वोट बैंक : साय

55 से 60 साल तक सत्ता में रही, जनजातीय समाज के लिए क्या किया ?

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय समाज के विकास और बस्तर से नक्सलवाद के खत्मे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सरकार जनजातीय समाज के विकास और बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। साय ने कांग्रेस से उसके लंबे शासनकाल के दौरान जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों का हिसाब भी मांगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने लगातार जनजातीय समाज को वोट बैंक के रूप में



इस्तेमाल किया, आज वही जनजातीय समाज कांग्रेस से दूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब जनजातीय समाज विकास और अपने अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है।

सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से बस्तर

क्षेत्र में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने इसे सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा एवं विकास से जुड़ी नीतियों का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए भारत सरकार में अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के विकास के लिए काम किया जा रहा है।

एशियन पैरा गेम्स में छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम परचम, तोमन और शीतल देवी ने रचा इतिहास

■ वित्त मंत्री चौधरी ने दी बधाई, कहां-प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा और संकल्प को मिल रही अंतरराष्ट्रीय पहचान

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में पैरा तीरंदाजी की कंपाउंड मिक्सड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी और छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ी तोमन कुमार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर भारतीय तिरंगे की शान बढ़ाने वाली यह स्वर्णिम उपलब्धि पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का क्षण है।

श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेटे तोमन कुमार ने शीतल देवी के साथ शानदार तालमेल, सटीक निशानेबाजी और अद्भुत एकाग्रता का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं की क्षमता, परिश्रम और दृढ़ संकल्प को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। छत्तीसगढ़ के



खिलाड़ी का एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना प्रदेश के खेल जगत के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि तोमन कुमार और शीतल देवी की सफलता केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहस, आत्मविश्वास और चुनौतियों पर विजय पाने की प्रेरणादायी कहानी भी है। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से साबित किया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।

निजी कार्यक्रम छोड़ केल्हारी बस दुर्घटना के घायलों से मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री

रायपुर। केल्हारी बस दुर्घटना में घायल लोगों का हालचाल जानने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल आज अपने सभी निजी कार्यक्रम स्थगित कर मनेन्द्रगढ़ स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने उपचाररत मरीजों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और बेहतर उपचार का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों से प्रत्येक घायल की स्वास्थ्य स्थिति एवं उपचार की जानकारी ली तथा समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है। संकट की इस घड़ी में सरकार दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देशित किया कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न हो और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी की जाए।



उल्लेखनीय है कि कल हुई केल्हारी बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और अनेक लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी हैं। घायलों को घोषणा की थी। जायसवाल ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना की।

टीएल बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने आयुक्त मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश

■ निर्धारित लक्ष्य अनुसार राजस्व वसूली कार्य करने को प्राथमिकता देने कहा

रायपुर। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक समयसीमा टी एल बैठक लेकर सभी कार्यों एवं योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मिश्रा ने रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के कार्य को प्राथमिकता देने कहा है। आयुक्त ने टीएल बैठक में सफाई सम्बंधित प्राप्त जनशिकायतों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किया। आयुक्त ने सफाई के पूर्व और सफाई के पश्चात की प्रमाण फोटो का अवलोकन किया। आयुक्त ने जोन कमिश्नरों को सफाई कार्य को प्राथमिकता देने कहा। आयुक्त ने बैठक में नगर निगम के हित को सर्वोपरि रखकर दिए

गए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली किये जाने को प्राथमिकता देने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। मिश्रा ने 31 दिसम्बर 2026 तक वर्तमान वर्ष के सम्पत्तिकर का पूर्ण भुगतान किये जाने पर सम्बंधित सम्पत्ति करदाता नागरिकों को नियमानुसार सम्पत्तिकर में 4 प्रतिशत की छूट देकर अधिक से अधिक संख्या में करों की वसूली कर सम्पत्ति करदाता नागरिकों को वांछित तौर पर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने बड़े बकायादारों से बकाया राजस्व वसूली नियमानुसार सख्तीपूर्वक करने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।

आयुक्त संबित मिश्रा ने नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण तय समयसीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित करने के सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए। आयुक्त ने अवैध नल कनेक्शनों को करारोपण में



सम्मिलित कर नल कनेक्शन नियमानुसार निर्धारित अर्थदंड लेकर नियमित करते हुए प्रक्रिया के अंतर्गत सम्बंधितों से जलकर की वसूली करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने टीएल बैठक में नगर निगम विभाग द्वारा ई चालान और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई चालान की कार्रवाई का अवलोकन किया। आयुक्त ने शहर में त्यौहार के पूर्व प्रकाश व्यवस्था को सुचारु बनाने के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है।

बीटीआई ग्राउंड में नहीं बनेगा कोई व्यावसायिक या आवासीय परिसर

रायपुर। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड को लेकर चल रही चर्चाओं पर रायपुर उत्तर विधायक के पुरंदर मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीटीआई ग्राउंड में किसी भी तरह का व्यावसायिक या आवासीय परिसर नहीं बनाया जाएगा।

विधायक पुरंदर मिश्रा के मुताबिक, परिसर का निर्माण बीटीआई ग्राउंड में नहीं, बल्कि उससे लगे सरकारी कर्मचारियों के जर्जर मकानों की जगह प्रस्तावित है। इन पुराने मकानों के स्थान पर परिसर बनाए जाएंगे।

बीटीआई ग्राउंड में व्यावसायिक या आवासीय निर्माण की चर्चाओं के बीच विधायक के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने ग्राउंड और उससे लगे सरकारी आवासों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्माण की योजना बीटीआई ग्राउंड के लिए नहीं है। बता दें कि गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायपुर के लोगों को ट्रैफिक के नाम पर प्रताड़ित करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजधानी में मंत्री और अधिकारी दो-दो बंगले रखे हुए हैं।

आईपीएस अंकिता शर्मा के समर्थन में भाजपा विधायक रिकेश सेन

कहा- देशभर में 100 से अधिक महिलाओं ने विजयदशमी पर की हर्ष फायरिंग

रायपुर। विजयादशमी के दिन साड़ी पहनकर हर्ष फायरिंग मामले में भाजपा विधायक रिकेश सेन ने राजनांदागांव एसपी आईपीएस अंकिता शर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने आईजी अजय यादव के बयान पर आपत्ति भी जताई है।

विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि पूरे भारत देश में 100 से ज्यादा महिलाओं ने विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजा कर गोली चलाई। इन 100 महिलाओं में एक भी आईपीएस नहीं थी। कोई जिला पंचायत सीईओ थीं, कोई जिला कलेक्टर थीं, कोई नगर निगम कमिश्नर थी, कोई एसडीएम थी, कोई अपर कलेक्टर थी। ये सब लोग भी साड़ी में ही थे, जिसका जीता जागता उधारण उज्जैन है।

विधायक रिकेश सेन ने कहा है कि राजनांदागांव आईजी अजय



यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा सोशल मीडिया में नकारात्मक कमेंट आने के कारण आईपीएस अंकिता शर्मा को नोटिस दिया गया। आईजी साहब सोशल मीडिया के हिसाब से पुलिस अगर चलेगी तो शायद स्मार्ट पुलिस बन पाना मुश्किल है। पुलिस को निर्णय अपने विवेक से अपनी सरकार की नीति से लेना पड़ता है।

भाजपा विधायक सेन ने आगे कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता शर्मा जी को जिस प्रकार से पूरा देश का मीडिया ट्रोल कर रहा है। इससे समझ आता है कि आज भी छत्तीसगढ़

को लेकर लोगों की मंशा ठीक नहीं है। मेरा समर्थन मजबूती के साथ आईपीएस अंकिता शर्मा के साथ है।

श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर (पीठाधीश्वर) अवधेशानंद गिरी महाराज ने भी अंकिता शर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अधिकारी अंकिता शर्मा के शस्त्र-पूजन ने प्रस्तुत किया- नारी-शक्ति, सांस्कृतिक स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठा का प्रेरक आदर्श। साड़ी में श्रद्धापूर्वक शस्त्र पूजन करते वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अधिकारी का स्वरूप भारतीय संस्कृति, नारी-गरिमा और राष्ट्रशा के संकल्प की सुंदर अभिव्यक्ति है।



खिलौने जमा करते हैं, जिनका उपयोग आंगनबाड़ी के बच्चों के मानसिक विकास और उनके सुपोषण के प्रति जनजागुरूकेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब तक इस पहल के अंतर्गत एक लाख से अधिक खिलौने जमा किए जा चुके हैं।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से चार सत्र आयोजित किए जाएंगे। विकसित भारत के लिए विशिष्ट प्राथमिकताएं और उद्देश्य, आर्थिक विकास एवं राज्य के वित्त को मजबूत बनाने में खनन क्षेत्र की भूमिका, सुशासन में तकनीक का प्रभावी उपयोग, सड़क व अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए एन विचार और बेहतर कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं पोषण, गैर- कृषि कार्यों में उर्वरकों के दुरुपयोग पर नियंत्रण,

प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, खाद्य विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, कौशल विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस., राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आंबिदी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, आदिम जाति विभाग के सचिव भूवनेश यादव, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्यो, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा, तथा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जनप्रतिनिधियों और आम जनता से नगर निगम रायपुर को प्राप्त जनशिकायतों का त्वरित निदान प्राथमिकता से तय समयसीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित करने निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जोन कमिश्नरों के निर्माण की प्रगति और मुख्यालय नगरोत्थान योजना अंतर्गत कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और कार्य को गतिमान रखकर शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।

आयुक्त संबित मिश्रा द्वारा ली गयी टी एल बैठक के दौरान अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के। शर्मा, विनोद पाण्डेय, रवि राही, मुख्य अभियंता संचय बागड़े, अधीक्षण अभियंता इमरान खान, नगर निवेशक आशु मिश्रा, सभी उपायुक्तों, जोन कमिश्नरों, सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों, कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, आईटी एक्सपर्ट रंजीत रंजन, सभी जोन सहायक राजस्व अधिकारियों, नगर निगम मुख्यालय के विभागों के अन्य सम्बंधित नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

सिर्फ चुनाव चोरी के शोर से जनादेश उलटा नहीं जा सकता

एस प्रसन्नराजन

दिल्ली में पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में आ गए, तो उस समय भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा नहीं हो रही थी; बल्कि यह एक रूपक का ऐसा बदला था, जिससे बड़ा बदला शायद ही कोई हो सकता था। यह गुस्सा (भले ही हताशा विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की हो) असल में व्यवस्था की कमियों के खिलाफ था। उच्च शिक्षा के ढांचे में मौजूद खामियों के विरोध में उठा यह कदम, काफी हद तक असहमति का एक स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन था। अगर सरकार ने जंतर-मंतर पर आंदोलन के पहुंचने से पहले अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होती, तो वह अपनी साख बचा सकती थी। मौजूदा विरोध-प्रदर्शन किसी जज की अलंकारिक टिप्पणी से नहीं, बल्कि खोजी पत्रकारिता से पैदा हुआ है। इसने कॉकरोच जनता पार्टी को भारत का सबसे मीडिया-फ़ंडली (मीडिया के अनुकूल) विपक्ष बना दिया है—खासकर संदेश मीडिया-फ़ंडली (मीडिया के अनुकूल) विपक्ष बना दिया है। खासकर संदेश मीडिया-फ़ंडली (मीडिया के अनुकूल) विपक्ष बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत चीजों को अपने भीतर समाहित कर लेने की क्षमता में दिखती है। इसने विपक्ष को एक ऐसा मंच दिया, जहां उन्हें अपने चुनावी जनाधार के अनुपात से कहीं ज्यादा मीडिया कवरेज मिल गया। फिर भी, इस उभार की विसंगतियां (जिन्हें सोशल मीडिया ने और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है) उतनी ही साफ नजर आती हैं, जितनी कि उस पीढ़ी की बेचैनी, जो दुनिया के अन्य हिस्सों में सड़कों पर उतरे लोगों से प्रेरित है। कॉकरोच अपने विरोध को—अगर दक्षिणपंथी तानाशाही नहीं, तो कम से कम—दबी हुई लोकतांत्रिक-व्यवस्था के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में पेश करना चाहेंगे। लंबे समय से, इस देश में असहमति की जो एक ऊंची छवि बनी रही, उसे उन पचा-लेखकों ने बनाए रखा, जो अपने लिखे शब्दों के अनुकूल कोई मुद्दा खोजते रहते थे; जबकि उनके ये शब्द खुद उन विचारधाराओं से प्रेरित थे, जिन्हें इतिहास ने बहुत पहले ही त्याग दिया है। अपनी अंतरीय स्थिति पैदा करने के लिए बेताब थे, जिसका वास्तविक भारत से कोई लेना-देना न हो। हो सकता है कि इन कॉकरोचों में उन असंतुष्ट लोगों जैसी बौद्धिक स्पष्टता न हो, जो भारतीय दक्षिणपंथ के उभार को लोकतंत्र की क्विक्टि के रूप में देखते हैं; लेकिन पहली बार चोट पहुंचाने के कुछ ही समय बाद, ये लोग सड़कों पर उसी भावना का एक व्यापक रूप बन गए हैं। जिस भारत के खिलाफ वे आक्रोश जताते हैं, वह उस भारत से मेल नहीं खाता, जिसकी कल्पना कुछ नौसिखिवा क्रांतिकारी अपनी भोली-भाली निष्कपटता में करते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप, चाहे उनमें कितनी भी सच्चाई क्यों न हो, भारतीय लोकतंत्र के अवैध होने की ओर इशारा नहीं करते। ये आरोप दिखाते हैं कि विपक्ष भारतीय मतदाताओं के कठोर रुख का सामना करने में असमर्थ है। चुनाव चोरी का शोर मचाना हार मान लेने की निशानी है। यह किसी नई संपूर्ण क्रांति की शुरुआत नहीं है। यह भूल जाइए कि जेपी (जयप्रकाश नारायण) जैसी कोई बड़ी नैतिक शक्ति नेतृत्व करने के लिए मौजूद है। यहां तक कि पुराने दौर के केजरीवाल जैसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, जो सड़क पर महात्मा की भूमिका निभा सके। हाशिये पर धकेले गए और बेकार हो चुके लोग, %कॉकरोचों% का सहारा लेकर, भाजपा सरकार को मिले भारी जनादेश को झूठ साबित करने की उम्मीद कर रहे हैं। नुक़ड़ नाटक या सड़क पर किए जाने वाले प्रदर्शन उन्हें टेलीविजन स्क्रीन से आगे नहीं ले जा पाएंगे। यह समय तर्क तैयार करने का है, न कि हारने के डर से अपने आरोप दोहराने का।

भारतीय दार्शनिक समुदाय

20-सर्वास्तित्वाद (वैभाषिक)

गतांक से आगे...

दूसरे शब्दों में उन्होंने सर्वास्तित्वाद को बाह्यार्थवाद के अर्थ में लिया है। शङ्कराचार्य ने भी अपने वेदान्त के शारीक भाष्य में (2।2।118) में ऐसा ही दिखाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के लेखकों ने शून्यवाद और विज्ञानवाद की अपेक्षा से हीनयान के पुराने थेरावादियों को और सर्वास्तित्वादियों को लगभग एक ही मान लिया है। और उनका नाम सर्वास्तित्वादी रख दिया है। यह स्पष्ट ही है कि वे लोग सर्वास्तित्वाद के थेरावाद आदि सम्प्रदायों से सूक्ष्म विवेचन से अनभिज्ञ थे। वस्तुत: यह स्पष्ट है कि सर्वास्तित्वाद नाम विज्ञानवाद और शून्यवाद की अपेक्षा से नहीं पड़ा था, प्रत्युत थेरावाद से किसी विशेष सैद्धान्तिक भेद से यह नाम पड़ा था। श्रेश्वात्स्की ने इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। परन्तु दर्शनशास्त्र की सामान्य भूमिका के इस निबन्ध में, उसकी गहराई में जाने का अवसर नहीं है। तथापि

मुख्य अन्तर की ओर संक्षिप्त संकेत कर देना भी आवश्यक ही है।

ऊपर थेरावाद के सिद्धान्त के निरूपण में यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक धर्म (वस्तु) केवल एक क्षण के लिए प्रतीत होता है अर्थात् केवल एक क्षण के लिए उसका अस्तित्व होता है। सर्वास्तित्वादियों ने कहा कि धर्मों का अस्तित्व दो प्रकार का है अर्थात् दो भिन्न भिन्न स्तरों पर है। एक धर्मस्वभाव है और दूसरा धर्मलक्षण है। इनमें पहिला अर्थात् धर्मस्वभाव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में रहता है। परन्तु दूसरा अर्थात् धर्मलक्षण धर्म का अपने क्रियाक्ष्म बाह्य दृश्यमान रूप में प्रादुर्भाव है जो केवल एक ही क्षण के लिए होता है। यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार सर्वास्तित्वाद पर किसी स्थिर नित्य धर्म को मानने का दोष आता है जो कि बौद्ध धर्म के मौलिक मन्तव्य के विपरीत है।

क्रमशः...



दिल्ली में बैठे बैठे मोदी ने इराक में कर दिया खेल

नीरज कुमार दुवे

दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है, वेनेजुएला से कितना तेल खरीदेगा और अमेरिकी दबाव के आगे भारत अपने फैसले बदलेगा या नहीं। लेकिन इस पूरे शोर-शराबे के बीच एक बड़ा सवाल जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है कि इराक से भारत कितनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इस खरीद से अपने आर्थिक हितों को कैसे साध रहा है? देखा जाये तो रूस और वेनेजुएला के तेल पर दुनिया बहस करती रहे, लेकिन भारत की असली रणनीति समझनी है तो इराक के साथ उसके तेल कारोबार पर नजर डालनी होगी। यही वह मोर्चा है, जहां भारत अपनी जरूरत, बाजार और कीमत के हिसाब से फैसले लेकर दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी के दबाव से नहीं, बल्कि देश के हितों से तय होती है।

देखा जाये तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, उद्योग और आम आदमी के जीवन में पेट्रोलियम की अहम भूमिका है। ऐसे में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि भी भारत के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव डाल सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में इराक ने भारत को 4.711 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा तेल उपलब्ध कराया। यह भारत के कुल तेल आयात के मूल्य का लगभग 19.16 प्रतिशत था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि इराक भारत के लिए कोई मामूली या वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता नहीं है। वह भारत की ऊर्जा व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। भारतीय तेल कंपनियां इराक से नियमित रूप से तेल खरीदती हैं और इस व्यापार के माध्यम से दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी मजबूत होते हैं।

इराक से भारत की खरीद का महत्व हाल के घटनाक्रमों से और बढ़ गया है। 22 अक्टूबर की



रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में भारत ने इराक से प्रतिदिन लगभग 8.30 लाख बैरल तेल आयात किया, जबकि अगस्त में यह मात्रा लगभग 1.71 लाख बैरल प्रतिदिन थी। इसी दौरान भारत का रूस से तेल आयात लगभग 14 प्रतिशत घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। यह बदलाव बताता है कि भारत की तेल खरीद किसी एक राजनीतिक समीकरण से तय नहीं होती। जब मध्य-पूर्व का तेल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होता है, तो भारतीय रिफाइनरियां उसकी ओर रुख कर सकती हैं। रूस का तेल भी भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण बना रहता है, लेकिन खरीद का फैसला कीमत, परिवहन खर्च, उपलब्धता और रिफाइनरी की जरूरतों के आधार पर होता है।

इस रणनीति का एक और उल्लेखनीय उदाहरण सामने आया। इसी महीने की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इराक के बसरा टर्मिनल से लगभग 20 लाख बैरल बसरा मीडियम क्कूड की एक खेप खरीदने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट में इस खरीद के लिए दुबई के तेल मूल्य से 32 डॉलर प्रति बैरल कम कीमत का उल्लेख किया गया। यह उदाहरण उस मूल सिद्धांत को सामने लाता है जिस पर भारत की ऊर्जा रणनीति आधारित होनी चाहिए। यानि जहां बेहतर आर्थिक शर्तें मिलें, वहां से तेल खरीदने के विकल्प खुले रखे जाएं।

देखा जाये तो तेल बाजार में भारत जैसे बड़े खरीदार का निर्णय केवल उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। भारत प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का आयात करता है। इसलिए यदि भारतीय कंपनियां रूस के बजाय इराक या दूसरे मध्य-पूर्वी

ज्ञान/मीमांसा

सपा की सियासत में आजम की ताकत और जेल का सियासी फलसफा

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामपुर की जेल सिर्फ एक चारदीवारी नहीं, बल्कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के भविष्य और मुस्लिम सियासत के नए ध्रुवीकरण का केंद्र बन चुकी है। 22 अक्टूबर 2026 को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के सबसे कड़ावर मुस्लिम चेहरे आजम खान के बीच रामपुर जिला जेल में हुई लगभग एक घंटे की मुलाकात केवल दो नेताओं की शिक्षाचार भेंट नहीं थी। यह उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात पर चली गई एक ऐसी चाल है, जिसके दूरगामी परिणाम न केवल समाजवादी पार्टी के भीतर, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर दिखाई देंगे। कानूनी शिकंजे में फंसे और चुनावी राजनीति से तकनीकी रूप से दूर हो चुके आजम खान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक इशारे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दर्जनों सीटों का गणित बदल सकता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव को खुद रामपुर जेल पहुंचकर यह संदेश देना पड़ा कि समाजवादी पार्टी में आजम खान की हैसियत न तो कम हुई है और न ही उन्हें हाशिए पर धकेला जा सकता है। यह मुलाकात इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सत्ता और कानूनी मुकदमों के उतार-चढ़ाव के बावजूद, सपा की सियासत में आजम की ताकत का सूरज पूरी तरह अस्त नहीं हुआ है, बल्कि रामपुर जेल की सलाखों के पीछे से वह एक नई ऊर्जा के साथ उभर रहा है। यह घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि जब-जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन या बड़े राजनैतिक उलटफेर की नींव रखी जाती है, तब-तब रामपुर का किला और वहां का नेतृत्व स्वतः ही मुख्यधारा की चर्चा के केंद्र में आ जाता है।

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए समाजवादी पार्टी के अंतर्विरोधों और उत्तर प्रदेश के बदलते मुस्लिम नेतृत्व के संकट को देखना जरूरी है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा आम थी कि आजम खान के जेल जाने और उनके परिवार पर आए कानूनी संकट के दौरान समाजवादी पार्टी ने उस आक्रामकता के साथ उनका साथ नहीं दिया, जिसकी उम्मीद एक संस्थापक सदस्य को होती है। पार्टी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर सुनागुहाट थी कि अखिलेश यादव अपनी छवि को एक नए, आधुनिक और गैर-विवादास्पद रूप में ढालने के लिए माई (मुस्लिम-यादव) समीकरण से थोड़ा इतर



पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दे रहे हैं। इस नए विमर्श में आजम खान जैसे पुराने समाजवादी दिग्गजों की कट्टर छवि फिट नहीं बैठ रही थी। इसी बीच, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और अन्य क्षेत्रीय दलों ने इस खालीपन को भरने की कोशिश शुरू कर दी। ओवैसी लगातार यह आरोप लगाते रहे कि सपा मुस्लिमों के वोट तो लेती है, लेकिन जब उनके बड़े नेताओं पर संकट आता है, तो नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कभी आजम खान का अभेद्य किला माना जाता था, वहां मुस्लिम मतदाताओं के बीच उपजे इस असमंजस को अखिलेश यादव भांप चुके थे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव और उसके बाद के घटनाक्रमों में जिस तरह से अंदरूनी गुटबाजी सामने आई, उसने पार्टी आलाकमान को सचेत कर दिया कि आजम खान को नजरअंदाज करने की कीमत 2027 में बेहद भारी पड़ सकती है। इसलिए, अखिलेश यादव का रामपुर जेल जाना राजनीतिक मजबूरी भी था और एक सोची-समझी रणनीति भी, जिसके जरिए उन्होंने एक ही झटके में ओवैसी के नैरेटिव को ध्वस्त करने और अपने कोर वोटर को यह भरसा दिलाने का प्रयास किया कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) के दौर के स्तंभ आज भी उतने ही आदरणीय हैं। यह कदम यह भी स्पष्ट करता है कि सपा अपने पारंपरिक और फायदार वोट बैंक को किसी भी अन्य वैचारिक प्रयोग की वेदी पर होम करने के लिए तैयार नहीं है।

जेल की इस मुलाकात ने न केवल सपा के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान पर भी एक तरह से विराम लगाने का काम किया है। हाल के दिनों में रामपुर के वर्तमान सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के समर्थकों के बीच की दूरी जगजाहिर रही है। स्थानीय स्तर पर संगठन दो धड़ों में बंट नजर आ रहा था। अखिलेश यादव ने जेल से बाहर आकर जिस तरह आजम

थे, आजम हैं और आजम रहेंगे का हुंकार भरा, उससे उन्होंने यह साफ कर दिया कि रामपुर और पूरे रूहेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का चेहरा और कमान आज भी परोक्ष रूप से आजम खान के पास ही रहेगी। खबरों के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने अखिलेश यादव को संभावित उम्मीदवारों और रणनीतिक बदलावों की एक सूची भी सौंपी। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के स्वरूप तक, आजम खान की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भले ही आजम खान खुद चुनावी मैदान में न उतर सकें, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल यूपी की सियासत में बेहद प्रभावी रहने वाला है। उनका यही प्रभाव अखिलेश यादव को उनके पास खींच लाया, क्योंकि वे जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज में आजम खान की आवाज आज भी एक भावनात्मक अपील रखती है, जिसे कोई दूसरा नेता रिफ्लेस नहीं कर पाया है। यह प्रभाव केवल रामपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली और अमरोहा जैसे पूरे मुस्लिम बहुल बेल्त में आजम खान की राजनीतिक छत्रछाया आज भी टिकटार्थियों के भाग्य का फैसला करने की क्षमता रखती है।

दूसरी तरफ, इस मुलाकात ने विपक्षी खेमे, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सपा पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। भाजपा ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति का नया अध्याय और अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश करार दिया है। सत्ताधारी दल का तर्क है कि कानून सम्मत कार्रवाई के तहत जेल में बंद एक सजायाफ्ता नेता से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की यह मुलाकात यह दर्शाती है कि सपा आज भी अपने पुराने ढर्रे और तुष्टिकरण की नीति से बाहर नहीं निकल पाई है। भाजपा के रणनीतिकार इस मुलाकात को बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच भुनाने की कोशिश करेंगे, ताकि सपा के खिलाफ एक बार फिर ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा सके। भाजपा के लिए यह मुलाकात एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वे यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ एक मुखौटा है, और असलियत में वे उसी पुरानी राजनीति की ओर लौट रहे हैं जिसे जनता ने नकारा था। सुभासपा और अन्य छोटे दलों ने इसे केवल एक चुनावी नौटंकी बताया है। विपक्ष का यह तीखा हमला दिखाता है कि वे भी

अच्छी तरह जानते हैं कि आजम और अखिलेश का यह पुनर्मिलन अगर जमीन पर रंग लाया, तो विपक्षी दलों के लिए मुस्लिम वोटों में संंध लगाना नामुमकिन हो जाएगा। भाजपा की ओर से आने वाले तीखे बयान इस बात का भी संकेत हैं कि वे आने वाले समय में कानून-व्यवस्था के मुद्दे को एक बार फिर चुनाव के केंद्र में लाएंगे और आजम खान का नाम लेकर सपा को घेरने की हरसंभव कोशिश करेंगे।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या रामपुर जेल की यह मुलाकात समाजवादी पार्टी को 2027 की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएगी? उत्तर प्रदेश की सियासत अब 2012 या 2017 जैसी नहीं रह गई है। मतदाता बेहद जागरूक हैं और केवल भावनात्मक अपीलों पर वोट नहीं करते। आजम खान की ताकत का एक पहलू अगर उनका भारी जनसमर्थन है, तो दूसरा पहलू उनकी छवि को लेकर होता है कि वे आला काउंटर-ध्रुवीकरण भी है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह होगी कि वे आजम खान की ताकत का इस्तेमाल मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में तो करें, लेकिन इसके साथ ही बहुसंख्यक और गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं को छिटकने न दें। पीडीए का जो गुलदस्ता अखिलेश ने तैयार किया है, उसमें आजम खान की हिस्सेदारी को इस तरह पिरोना होगा कि वह समावेशी दिखे, न कि केवल एक बड़े विशेष की राजनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट-मुस्लिम-दलित गठबंधन सपा बनाने का प्रयास कर रही है, उसमें आजम खान की स्वीकार्यता को संतुलित रखना एक बेहद बारीक राजनीतिक कला होगी। यदि सपा इस संतुलन को साधने में सफल रही, तो रामपुर जेल से शुरू हुआ यह सफर 2027 में लखनऊ के सचिवालय तक पहुंच सकता है, अन्धथा ध्रुवीकरण की तेज हवा इस पूरी रणनीति को बिखेर भी सकती है। बहरहाल, रामपुर जेल के बंद कमरों से निकला यह सियासी संदेश उत्तर प्रदेश की वादियों में गूँजने लगा है। इसने यह तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में रामपुर की धरती एक बार फिर सूबे की राजनीति का कुरुक्षेत्र बनेगी। आजम खान जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सपा की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बने हुए हैं, और अखिलेश यादव के इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता आज भी रामपुर के सियासी गलियारों से होकर ही गुजरता है।

मुश्किल गायिकी में मन्ना डे को हासिल थी महारत

अनन्या मिश्रा

जब भी हिंदी फिल्मों के सदाबहार गीतों की बात की जाती है, तो कुशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ मन्ना डे का नाम भी लिया जाता है। बता दें कि मन्ना डे की आवाज इतनी मधुर और पहचानने वाली थी कि एक समय को श्रोता फिल्मों के नाम भले ही भूल जाएं, लेकिन मन्ना डे के गाए गीत नहीं भूलते। आज ही के दिन यानी की 24 अक्टूबर को गायक मन्ना डे का निधन हो गया था। लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीतों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 01 मई 1919 को मन्ना डे का जन्म हुआ था। इनका असल नाम प्रबोध चंद्र डे था। मन्ना डे ने फिल्म इंडस्ट्री में अपन करियर की शुरुआत साल 1942 में आई फिल्म तमन्ना

से की थी। इस फिल्म में उन्होंने फेमस गायिका सुरैया के साथ गाया था। इसके बाद साल 1943 में आई फिल्म राम राज्य में गई तू गई सीता सती गाया था, जिसकी महात्मा गांधी ने भी सराहा था।

बता दें कि मन्ना डे

की यह खासियत थी कि वह मुश्किल और चुनौतीपूर्ण गानों को सहजता से गा लेते थे। संगीतकारों ने उनकी गायकी क्षमता को देखते हुए हमेशा कठिन गीतों के लिए मन्ना डे का चयन किया था।

वहीं राजकपूर ने भी कई फिल्मों में मन्ना डे को चुना। उन्होंने साल 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी में गीत ये रात भीगी भीगी को मुकेश की जगह मन्ना डे और

लता मंगेशकर से रिकॉर्ड कराया था। यह गीत आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गीतों में से एक माना जाता है।

मन्ना डे के गायन की तारीफ उनके समकालीन कलाकारों ने भी किया था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी भी मन्ना डे के गीतों के

कायल थे। लता मंगेशकर ने मन्ना डे को उपकार फिल्म के कसमें वादे प्यार वफा के लिए बेहद सराहा था।

मन्ना डे ने संगीत की दुनिया में खूब नाम कमाया था। वह सिनेमा जगत के ऐसे गायक थे, जिनके फैन मोहम्मद रफी भी हुआ करते थे। वहीं मन्ना डे अभिनेता राजेश कपूर के फैन थे। उन्होंने अधिकतर गाने राजेश खन्ना के लिए गाए थे। राजेश खन्ना

जिस तरह से गाने को फिल्माते थे, वह अंदाज मन्ना डे को काफी पसंद आता था। एक बार तो गायक ने कह दिया था कि वह हमेशा राजेश कन्ना के कर्जदार रहेंगे। क्योंकि उनके द्वारा गाए गानों को राजेश खन्ना जिंदादिल बना देते थे।

मन्ना डे ने हिंदी और बॉला के अलावा कुल 14 भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्होंने 5 दशकों के अपने करियर में करीब 3,046 गाने रिकॉर्ड किए। उनके फेमस गीतों में जिंदगी कैसी ये पहली, यारी है ईमान मेरा प्यार मेरी जिंदगी, कसमें ये वादे प्यार वफा, तू थार का सागर है, ये दोस्ती, जिंदगी कैसी है पहली, आ जा सनम मधुर चांदनी, यशोमति मैया से, एक चतुर नार और प्यार हुआ इकरार हुआ शामिल हैं।

वहीं 24 अक्टूबर 2013 को मन्ना डे ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।

आज का इतिहास

1648 फ्रांस–ऑस्ट्रिया स्वीडन और फ्रांस के मध्य वेस्टफाली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

1657 कल्याण और भिवंदी के शासन के अधीन आए थे।

1793 फ्रेंच रिपब्लिकन कैलेंडर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था।

1795 पोलैंड को ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस के बीच विभाजित किया गया था।

1851 कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी।

1861 कैलिफ़ोर्निया के जस्टिस स्टीफन जे फील्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंक्न को पहला अंतरमहाद्वीपीय टेलीग्राफ संदेश भेजा था।

1915 न्यूयॉर्क में 25 हजार महिलाओं ने मतदान के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया था।

1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति के लिए 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी।

1946 पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया था।

1947 पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में स्थापित किया था।

1948 बर्नाई बारूक ने सीनेट युद्ध की जांच समिति के समक्ष एक भाषण में पहली बार शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया था।

1949 न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की आधारशिला रखी गई थी।

1964 उन्नी रोडेशिया जांबिया गणतंत्र बना कैनेथ कौंडा वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने थे।

1975 बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था।

1982 सुधा माधवन मैराथन में दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनीं थी।

1984 कोलकाता में एस्पेलेनाड और भवानीपुर के बीच पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी।

2000 दक्षिण कोरिया द्वारा लम्बी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण न करने की घोषणा की थी।

2001 नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया था।

2003 लंदन में आखिरी वाणिज्यिक सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान उतरा था।

2004 बाजील ने अंतरिक्ष में पहला सफल रॉकेट परीक्षण किया था।

2005 न्यूजीलैंड–भारत नया हवाई सेवा समझौता करने पर सहमत थे।

दक्षिण की राजनीति में बदलाव के संकेत

सौरभ तार्षणेय

केंद्र सरकार के विधायी एजेंडे का समर्थन करने वाले दक्षिण भारतीय दलों का चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर होना बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। एसआईआर, वोट चोरी के आरोप और चुनावी निष्पक्षता पर उठते सवालों के बीच आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष की रणनीति और सहयोगी दलों का रुख महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारतीय राजनीति में बदलाव की आहट अब केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि दक्षिण भारत के राजनीतिक गलियारों में भी नए समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। जिन क्षेत्रीय दलों ने संसद में कई मौकों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उनमें से कुछ का चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अधिक मुखर होना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि क्या यह केवल अपने राज्यों के राजनीतिक हितों की रक्षा का प्रयास है, या इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति में बदलते जनमत और सत्ता के समीकरणों का भी संकेत छिपा है?

दक्षिण भारत की राजनीति लंबे समय से अपनी अलग पहचान रखती है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मतदाताओं के मुद्दे, क्षेत्रीय अस्मिता, सामाजिक न्याय, भाषा, विकास और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका चुनावी परिणामों को प्रभावित करती रही है। यहां किसी राष्ट्रीय दल के लिए केवल राष्ट्रीय लोकप्रियता के आधार पर राजनीतिक बहुत बनाए रखना आसान नहीं होता। क्षेत्रीय दलों की मजबूत जड़ें और स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता केंद्र की राजनीति में भी उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती हैं।

एलन मस्क की खुराफात को समझना जरूरी?

विकास मिश्रा

दुनिया के जाने-माने उद्योगपति और स्पेस की दुनिया के खिलाड़ी एलन मस्क पिछले दिनों भारत को लेकर बहुत खफा नजर आए। उन्होंने भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी पर आरोप लगाए कि भारत में स्टारलिक को अनुमति नहीं मिलने के पीछे वही हैं। हालांकि सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि प्रक्रिया चल रही है और भारत अपनी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के नियमों को गढ़ने के बाद ही किसी को भी स्पेस इंटरनेट की अनुमति देगा। अंबानी ने भी मस्क को करारा जवाब दिया कि वे प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते हैं। मगर हमारी चर्चा का विषय फिलहाल यह है कि एलन मस्क ने जो आरोप लगाए, उसके पीछे क्या केवल उनकी व्यापारिक चिंता है या फिर मामला कुछ और है? केवल व्यापारिक चिंता होती तो वे शायद इतना नहीं बिलबिलाते और भारत सरकार के निर्णय का इंतजार करते। मगर वे तो भारी बेचैनी में हैं। तो क्या वक्त का कोई टुकड़ा उनके हाथों से फिसला जा रहा है? भारत सरकार क्या एलन मस्क की बेचैनी को समझ गई है? ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें वैश्विक राजनीति को बहुत ही सावधानीपूर्वक समझना होगा कि दुनिया के किन देशों में एलन मस्क किन सवालों के घेरे में हैं। उन पर किस तरह के खुराफात के आरोप लग रहे हैं! भारत के संदर्भ में सवालों के जवाब वहां तलाशे जा सकते हैं। यूक्रेन ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर आरोप लगाए हैं कि उसने यूक्रेन के सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होने वाले स्टारशील्ड सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क पर गति सीमा लगा दी है। इसे इस तरह समझिए कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज गति से चलने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी अत्यंत धीमी कर दी गई है। इसका नतीजा है कि यूक्रेन को हवाई हमले करने और रूसी ड्रोन्स को हवा में इंटरसेप्ट करने में कठिनाई आ रही है। इतना ही नहीं, रूस की मिसाइलों के हमलों की पहले से चेतावनी देने वाले

चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर उठ रहे सवाल अब व्यापक राजनीतिक बहस का विषय बनते जा रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची को शुद्धता और मताधिकार की सुरक्षा को लेकर सरकार तथा चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों ने भी इस बहस को राजनीतिक धार दी है। हालांकि, इन आरोपों को प्रामाणित तथ्य मानने के बजाय उनकी निष्पक्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और आयोग के जवाब के आधार पर परखना आवश्यक है।

ऐसे माहौल में यदि दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल भी खुलकर अपनी आपत्तियां सामने रखते हैं, तो इसे केवल विपक्षी राजनीति का विस्तार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह भी संभव है कि इन दलों को अपने राज्यों में मतदाता सूची, संघीय अधिकारों और चुनावी प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दबाव महसूस हो रहा हो। उनके रुख से यह संकेत जरूर मिलता है कि संसद में किसी मुद्दे पर सहयोग और चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाने के बीच राजनीतिक दल अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं।

यह प्रश्न आज राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है कि क्या मोदी लहर की लोकप्रियता और भाजपा की चुनावी पकड़ में पहले जैसी मजबूती नहीं रही। लेकिन किसी एक विरोध प्रदर्शन, प्रेस वार्ता या क्षेत्रीय दल के बदले हुए रुख को मोदी लहर के कमजोर पड़ने का निर्णायक प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। राष्ट्रीय राजनीति में लोकप्रियता का आकलन करने के लिए चुनावी नतीजों, जनमत सर्वेक्षणों, राज्यों के मुद्दों, गठबंधन की स्थिति और मतदाताओं के व्यवहार को समग्र रूप से देखना होगा।



यह जरूर है कि भारतीय मतदाता अब कई स्तरों पर राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता के साथ महंगाई, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय विकास, किसानों की समस्याएं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा भी महत्वपूर्ण हैं। यदि विपक्ष इन मुद्दों को जनता पर प्रभावी ढंग से जोड़ने में सफल रहता है, तो भाजपा के सामने चुनौती बढ़ सकती है। दूसरी ओर, भाजपा का संगठन, नेतृत्व और व्यापक चुनावी नेटवर्क भी उसकी राजनीतिक ताकत के महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए सवाल केवल मोदी लहर के कमजोर होने का नहीं, बल्कि यह है कि क्या विपक्ष अपने आरोपों और राजनीतिक नाराजगी को ठोस जनसमर्थन में बदलने की क्षमता विकसित कर रहा है।

कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध और वोट चोरी के आरोपों के माध्यम से चुनावी निष्पक्षता को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। इस रणनीति का उद्देश्य केवल केंद्र सरकार को घेरना नहीं, बल्कि मताधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े प्रश्नों को आम मतदाता तक पहुंचाना भी है। हालांकि, किसी आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जनता की वास्तविक चिंताओं से कितना जुड़ा है और उसके समर्थन में कितने विश्वसनीय तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं।

विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी अपनी

निरज कुमार दुबे

विपक्ष अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगाता रहता है लेकिन जो परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है वह दर्शा रहा है कि भारत की ताकत और मोदी की कूटनीति के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा है। चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हों, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हों या फिर अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क हों, आप उनके ताजा बयानों को देखेंगे तो पाएंगे कि रातोंरात अचानक उनमें बड़ा परिवर्तन आ गया है। भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर भारी टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अब अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद माना है कि भारत के साथ होने वाला व्यापार समझौता इस फैसले की एक बड़ी वजह है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि भारत की अपनी जरूरतें हैं और वह एकदम से रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता।

हम आपको बता दें कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अमेरिकी दबाव के बीच सबसे महत्वपूर्ण संकेत विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान से आया है। उज्बेकिस्तान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रूबियो ने स्वीकार किया कि रूस के तेल पर प्रतिबंधों में छूट देने के फैसले में भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते की अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने रूस से संबंधित प्रतिबंधों के प्रभावों का आकलन करने के लिए 60 दिनों की राहत दी है। रूबियो के



मुताबिक, अमेरिका को यह भी देखना होगा कि एक साथ प्रतिबंध और टैरिफ लगाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था और खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ?

यानी जिस रूस-तेल मुद्दे को भारत पर दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी पर अब वॉशिंगटन को अपने कदमों के परिणामों की चिंता सता रही है। मार्को रूबियो का यह कहना, ९९%भारत रूस से ऊर्जा आयात को एक झटके में बंद नहीं कर सकता। नई आपूर्ति व्यवस्था विकसित करने में समय लगता है और ऊर्जा की कीमतों में उछाल का सीधा असर आम लोगों तथा उद्योगों पर पड़ता है९%, दर्शा रहा है कि मोदी की कूटनीति कितनी कामयाब रही। साथ ही रूबियो ने यह भी स्वीकार किया कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है और उसकी ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

देखा जाये तो अमेरिका को इस बदली हुई रणनीति के पीछे घरेलू आर्थिक चिंताएं भी हैं। महंगे ईंधन का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने से वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले महंगाई

परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि किसी दल को लगता है कि केंद्र सरकार के साथ उसके संबंध उसके राज्य की राजनीति या जनाधार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वह अपना रुख बदलने पर विचार कर सकता है।

फिर भी, किसी दल की चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी या विरोध को केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने का संकेत मानना उचित नहीं होगा। इसके लिए दलों के आधिकारिक वक्तव्यों, संसदीय व्यवहार, गठबंधन संबंधों और ठोस राजनीतिक फैसलों को देखना जरूरी है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चुनावी सुधार, मतदाता सूची, संघीय संबंधों और चुनाव आयोग की जवाबदेही जैसे विषयों पर बहस की संभावना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। विपक्ष इन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर सकता है, जबकि सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर ध्यान देगी। क्या क्षेत्रीय दल इस दौरान अपना स्वतंत्र रुख अपनाएंगे और क्या संसद में नए राजनीतिक समीकरण दिखाई देंगे, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

दक्षिण भारत की राजनीति में बढ़ती मुखरता को भारतीय लोकतंत्र के बदलते राजनीतिक संवाद के रूप में देखा जा सकता है। यह केंद्र सरकार के लिए चेतावनी हो सकती है कि क्षेत्रीय दलों के समर्थन को स्थायी मानकर नहीं चला जा सकता। वहीं विपक्ष के लिए भी यह अवसर है कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करे। लेकिन मोदी लहर के कमजोर पड़ने, सहयोगी दलों के अलग होने या आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष की निर्णायक बढ़त जैसे निष्कर्ष अभी समय से पहले होंगे। वास्तविक तस्वीर चुनावी नतीजों, जनसमर्थन और राजनीतिक दलों के ठोस फैसलों से सामने आएगी।

पीएम मोदी की कूटनीति पॉवर देखकर दुनिया हैरान

संभावित एंट्री के बीच मस्क ने सोशल मीडिया पर भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी और बाजार की प्रतिस्पर्धा से जुड़े आरोप लगाए थे। रिलायंस ने जवाब में कहा कि वह उपग्रह संचार सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है, लेकिन हर कंपनी को भारतीय कानूनों और नीतियों का पालन करना होगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि जियो की अपनी उपग्रह सेवाएं भी मंजूरियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके बाद मस्क ने रिलायंस की प्रतिक्रिया पर ‘Much appreciated’ कहकर जवाब दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वह मुंबई में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के अलावा गुजरात के जामनगर जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी की अवलोकन भी करेंगे। खास बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्हीं मुकेश अंबानी की है जिन्हें एलन मस्क ने भारत का प्रधानमंत्री बताया था।

बहरहाल, रूबियो, वेंस और मस्क के ढीले पड़ते तेवर और ट्रंप का बदला रख दर्शा रहे हैं कि दुनिया में भारत की कूटनीति कुछ भी हासिल कर सकती है। रूस से तेल खरीदने का सवाल हो, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो, एच-1बी वीजा विवाद हो या स्टारलिक की भारत में एंट्री का मुद्दा हो, इन सभी घटनाक्रमों के केंद्र में एक चीज स्पष्ट है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर बाहरी दबाव कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत ऐसा साझेदार नहीं है जिसके सामने केवल दबाव बनाकर मनचाहा फैसला हासिल कर लिया जाए। नई दिल्ली का संदेश स्पष्ट है कि रिश्ते मजबूत होंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, लेकिन फैसले भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही होंगे।

सी.जे.पी. ने अपनी क्षमता से कहीं बड़ा लक्ष्य चुन लिया

विपिन पब्ली

नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का वार्षिक विजयादशमी व्याख्यान और प्रधानमंत्री का इंद्रप्रस्थ रामलीला मैदान में संबोधन, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और उसके वैचारिक स्रोत में बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं।आर.एस.एस. प्रमुख के मन में स्पष्ट रूप से कांकिरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवाओं द्वारा हाल ही में किए गए विरोध-प्रदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष का विचार था, जब उन्होंने कहा कि समाज, न कि विरोध प्रदर्शन, बदलाव ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘बुरी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं।’

भागवत की टिप्पणियों से पता चलता है कि मोदी सरकार के कामकाज की शैली को लेकर आर.एस.एस. के जो भी मतभेद रहे हों, हाल के विरोध-प्रदर्शनों के मुद्दे पर संगठन पार्टी की सोच के साथ खड़ा है। इन प्रदर्शनों में अब तेजी से ‘सत्ता परिवर्तन’ की मांग उठाई जा रही है। एक असामान्य कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जो आमतौर पर आर.एस.एस. पर सांकेतिक रूप से टिप्पणी नहीं करते, ने कहा कि उन्हें भागवत का व्याख्यान ‘अत्यंत प्रेरणादायक’ लगा। राष्ट्रीय राजधानी में विजयादशमी समारोह के दौरान अपने भाषण में मोदी ने कहा कि जब देश के हित दांव पर हों, तो सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। भाजपा नेता देश में हाल के विरोध प्रदर्शनों के पीछे विश्वी ताकतों का हाथ होने का आरोप लगाते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि इन



प्रदर्शनों का वास्तविक उद्देश्य ‘सत्ता परिवर्तन’ का प्रयास है। विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते दायरे को देखते हुए यह चिंता उचित हो सकती है। फिलहाल विभिन्न कारणों से विरोध प्रदर्शनों में विराम आया है और यह देखना बाकी है कि विपक्षी दल या कॉंकिरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाला युवा आंदोलन फिर से अपनी गति हासिल कर पाता है या नहीं।

हालांकि, शुरूआती लामबंदी, जिसकी शुरूआत भारत के मुख्य न्यायाधीश की कॉंकिरोचों पर की गई टिप्पणी के आधार पर किए गए एक ट्वीट से हुई थी, पहले चरण का विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद से कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसका संकेत सी.जे.पी. नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट पर घटती प्रतिक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिक्रिया से मिलता है। सी.जे.पी. नेताओं की कई गलतियों के कारण युवा आंदोलन को मिलने वाला समर्थन घटता दिखाई दिया। पहली बात, संगठन ने खुद को उन राजनीतिक दलों से दूर कर लिया, जिनकी मांग भी वही थी। इतना ही नहीं, सीजेपी के

कुछ नेताओं ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी का मजाक भी उड़ाया।

दूसरी बात, देश के अन्य हिस्सों में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करने की बजाय नेतृत्व को मुख्य रूप से महाराष्ट्र तक सीमित रखना एक बड़ी गलती थी। अब यह संगठन दिखाहीन दिखाई देता है और इसका नेतृत्व स्पष्ट रूप से मानता है कि उसे दूसरों की सलाह या समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा दो शीर्ष नेताओं की हिरासत बढ़ाए जाने के साथ ही पार्टी अपनी दिशा खोती दिखाई दे रही है। हालांकि, अभी इसके अंत की घोषणा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन सीजेपी नेताओं को केवल इस्तीफों की मांग करने की बजाय युवाओं को आंदोलन से जोड़े रखने के तरीके खोजने होंगे। इसी संदर्भ में ‘सत्ता परिवर्तन’ की मांग का समर्थन करने के उसके फैसले की जांच की जानी चाहिए। यह मांग सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में उठाई गई थी और वामपंथी छात्र नेता नेहा बोरा ने इसका समर्थन किया था। इसके बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे अन्य ‘स्वतंत्र’ कार्यकर्ताओं ने भी इसका समर्थन किया। इनमें से कुछ लोग श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुए इसी तरह के जन आंदोलनों की ओर इशारा करते रहे हैं। यह सच है कि वे आंदोलन भी बिना किसी एक नेता के थे, युवाओं के नेतृत्व में चले थे और वास्तव में उनके परिणामस्वरूप ‘सत्ता परिवर्तन’ हुआ था।

हालांकि, यह मानना ​​​​मुख्यतापूर्ण होगा कि भारत में भी इस तरह का ‘सत्ता परिवर्तन’ लाया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे देश में सैन्य तख्तापलट होना असंभव है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र है। यह एक उपमहाद्वीप है, जहां अलग-अलग क्षेत्र, संस्कृतियां और सामाजिक समूह हैं। इसके अलावा, यहां लोकतंत्र की मजबूत परंपराएं हैं और हम सभी जानते हैं कि 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाए जाने से पैदा हुई असामान्य स्थिति के पीछे क्या कारण थे। पड़ोसी देशों में जहां इस तरह का ‘सत्ता परिवर्तन’ संभव हुआ, उसका कारण यह था कि वे छोटे देश हैं। वे देश भारत के कुछ राज्यों से भी छोटे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की बहुत-सी संस्थाओं, जिनमें निर्वाचन आयोग भी शामिल है, ने जनता का विश्वास खो दिया है, लेकिन ‘सत्ता परिवर्तन’ लागू करने का एकमात्र तरीका चुनावी प्रक्रिया है। विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, को यह साबित करना होगा कि वह केवल विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करके नहीं, बल्कि जनता के समर्थन से बदलाव ला सकती है। जहां तक सी.जे.पी. और उसके नेताओं का सवाल है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक बड़ा लक्ष्य चुन लिया है। वे शिक्षा प्रणाली में बदलाव ला सकते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ‘सत्ता परिवर्तन’ की मांग करने से उन्हें उस तरह का जनसमर्थन नहीं मिलने वाला, जैसा उन्हें उस समय मिला था जब वे तत्कालीन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

क्या आकार ले रही है नई इस्लामी सामरिक धुरी, भारत को रखनी होगी नजर

देवेश त्रिपाठी

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच मक्का संयुक्त रक्षा करार होने के करीब ढाई महीने बाद अब पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया के मध्य दोहा में हुए बद्र समझौते से यही स्पष्ट होता है कि वैश्विक राजनीति में इस्लामी धुरी किस दिशा में जा रही है। जिस तरह से ये देश एकजुट हो रहे हैं, उसे महज कुछ मुस्लिम देशों के बीच रक्षा सहयोग की सामान्य पहल मानकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनके जरिये पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया तक सामरिक हितों के नए समीकरण बनाने की कोशिश दिखाई देती है। गौरतलब है कि मक्का समझौते के तहत किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माने जाने का प्रावधान है। दूसरी तरफ, 21 अक्तूबर को दोहा में हुआ बद्र समझौता मुख्यतः रक्षा उद्योग, सैन्य उत्पादन, तकनीकी प्रशिक्षण व अनुसंधान एवं विकास में सहयोग से संबंधित है। लिहाजा, दोनों समझौतों एक ही तरह का सैन्य गठबंधन कहना उचित नहीं होगा। इसे इन देशों की अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश बताया जा रहा है, पर इन देशों के बीच उपरते सामरिक तालमेल के कुछ और अर्थ भी हो सकते हैं।

आखिर अलग-अलग हितों वाले मुस्लिम बहुल देशों ने साथ मिलकर हथियार बनाने का फैसला किया, तो क्या यह अपने आप में सोचने का विषय नहीं है? दरअसल, इन समझौतों के विषय में अहम सवाल यह भी है कि क्या ये देश अपनी सुरक्षा



संबंधी चिंताओं को साझा करते हुए एक प्रभावी सामरिक समूह बनाना चाहते हैं, या फिर इनके पीछे इस्लामी पहचान को अंतरराष्ट्रीय शक्ति में बदलने की कोई व्यापक रणनीति काम कर रही है। अगर दूसरी संभावना आकार लेती है, तो इसका असर न केवल पश्चिम एशिया, बल्कि भारत समेत उन सभी देशों पर पड़ सकता है, जिनके हित इस क्षेत्र की स्थिरता से जुड़े हैं।

हालांकि, फिलहाल इन्हें एक व्यापक इस्लामिक सैन्य गठबंधन का निर्णायक प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस सामरिक नेटवर्क की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। भारत के लिए इन घटनाक्रमों पर सतर्क निगाह रखना जरूरी है। उसके सऊदी अरब व कतर जैसे खाड़ी देशों के साथ गहरे आर्थिक संबंध हैं। साथ ही, वहां कार्यरत लाखों भारतीयों के हित भी जुड़े हुए हैं। बद्र समझौते को प्रत्यक्ष तौर पर भारत के विरुद्ध बना सैन्य गठबंधन घोषित करने का बेशक कोई आधार नहीं है, पर पाकिस्तान के अतीत और उसकी हरकतों के महेनजर इस्लामाबाद की किसी भी नई सामरिक साझेदारी का आकलन भारतीय सुरक्षा हितों के संदर्भ में करना जरूरी है।



दुनिया के इस खूबसूरत गांव में मौजूद है फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं, फिर भी नहीं है कोई रहने वाला

किजोंग-डोंग गांव साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मिलिट्रीरहित जोन में स्थित है। साल 1953 में कोरियन वॉर के बाद हुए युद्ध विराम के दौरान इस गांव को बनाया गया था। कई लोग इस गांव को प्रोपगेंडा विलेज कहते हैं। लोगों का ये मानना है कि इस गांव का निर्माण इसलिए कराया गया ताकि उथ कोरिया में रह रहे लोगों को ऐसा लगे कि यहां के लोगों की लाइफ काफी लजरी है।

किजोंग-डोंग का इतिहास

किजोंग-डोंग गांव के निर्माण का किस्सा भी काफी रोचक है। दरअसल,

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जब कोरियाई युद्ध की अनौपचारिक समाप्ति हुई, उसी समय इस गांव का निर्माण हुआ। तीन साल तक चले इस युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दोनों देशों को अलग करने वाले क्षेत्र को डिमिलिट्राइज एरिया के रूप में जाना जाता है। युद्ध के दौरान दोनों देशों ने यहां से अपने नागरिकों को हटा दिया था। युद्ध विराम की घोषणा के समय यह तय किया गया कि दोनों देश सीमा पर सिर्फ एक ही गांव को बरकरार रख सकते थे या फिर नया गांव बसा सकते थे। ऐसे

में दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा में मौजूद फ्रीडम विलेज के रूप में जाना जाने वाला डाइसॉनिंग-डोंग को बरकरार रखा। यहां पर करीब 226 लोग रहते हैं। इतना ही नहीं इस गांव के लोगों को विशेष पहचान पत्र दिया गया है और रात 11 बजे के बाद करफ्यू लग जाता है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने पीस विलेज के रूप में एक नया गांव किजोंग-डोंग का निर्माण करवाया। इस गांव को लेकर उत्तर कोरिया का ये

दुनियाभर में ऐसी कई जगहें हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कुछ ऐसी ही एक जगह है उत्तर कोरिया का किजोंग-डोंग गांव। खूबसूरती के मामले में इस गांव का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन यहां पर कोई रहने वाला ही नहीं है। हालांकि, इस गांव में आलीशान इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें, पानी की टंकी, बिजली, स्ट्रीट लाइट समते तमाम तरह की सुविधाएं हैं।

दावा है कि यहां पर 200 निवासी हैं। बच्चों के लिए किडरगार्टन, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अलावा यहां रह रहे लोगों के लिए अस्पताल भी है। लेकिन पर्यवेक्षकों के मुताबिक यह गांव एकदम सुनसान है और यहां कोई नहीं रहता है। लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए रोजाना घरों में लाइट जलाई जाती हैं और सड़कों पर सफाईकर्मी झाड़ू लगाते नजर आते हैं। लेकिन इस गांव में रहने वाले लोग नहीं दिखाई देते हैं।



पंख केवल उड़ान भरने में ही पंछियों की मदद नहीं करते। प्रकृति ने इन्हें इस तरह से बनाया है कि ये पक्षियों के लिए रेनकोट भी बनते हैं, दुश्मन से बचाव का साधन भी और हर पंछी की अपनी पहचान का माध्यम भी। साथ ही ये तापमान को नियंत्रित रखने में भी मदद करते हैं। पंखों की रचना और रंगों को देखकर मेल-फीमेल पक्षी का पता भी लगाया जा सकता है। पक्षियों के पंरों को अलग-अलग आकार-प्रकार के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जाता है।

प्रकृति की खूबसूरत कारीगरी पंख

पंछियों को उड़ने के लिए पंखों का तोहफा देने वाले नेचर ने वाकई अद्भुत कारीगरी दिखाई है। आओ इन पंखों को जाने और करीब से।

पर, पर हैं क्या?

पंख, पर या फैदर्स असल में पंछियों की ऊपरी त्वचा यानी स्किन पर उगने और उसे कवर करने वाली संरचना होते हैं। साइंस की भाषा में कहा जाए तो यह एपिडर्मिस के ऊपर होने वाली ग्रोथ है। साइंस यह भी कहता है कि रेप्टाइल्स के शरीर पर पाए जाने वाले स्केल्स ही असल में पक्षियों के शरीर पर पंखों के रूप में विकसित हुए हैं। पंछियों के अलावा ये कुछ अन्य प्राणियों के शरीर पर भी पाए जाते हैं। वहां इनका रूप भी अलग हो सकता है। पंख भी नाखून और बालों की ही तरह कैराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं।

उड़ो और बचो भी

पंख केवल उड़ान भरने में ही पंछियों की मदद नहीं करते। प्रकृति ने इन्हें इस तरह से बनाया है कि ये पंक्षियों के लिए रेनकोट भी बनते हैं, दुश्मन से बचाव का साधन भी और हर पंछी की अपनी पहचान का माध्यम भी। साथ ही ये तापमान को नियंत्रित रखने में भी मदद करते हैं। पंखों की रचना और रंगों को देखकर मेल-फीमेल पक्षी का पता भी लगाया जा सकता है। पक्षियों के पंरों को अलग-अलग आकार-प्रकार के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जाता है।

रंगों का मजेदार विज्ञान

पंछियों के पर क्रिप्टिक्टिटी के मामले में भी प्रकृति की खूबसूरत कारीगरी होते हैं। रंग-बिरंगे इंद्रधनुष से ये पंख वाकई इंद्रधनुष सी ही काबिलियत रखते हैं। तुम्हें ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि

फैदर्स में इंद्रधनुष के सारे रंग होते हैं। इनमें से ज्यादातर रंग एक खास पिगमेंट के कारण बनते हैं। यह क्रिया ठीक ऐसे ही होती है जैसे खाना बनाते समय फूड कलर्स को यूज करने पर होती है। जैसे कि जब तुम किसी पकवान में लाल या पीला रंग मिलाते हो तो वो लाल या पीले रंग का हो जाता है। ठीक उसी तरह पंखों में भी जिस रंग का पिगमेंट मौजूद होता है वो उसी रंग के नजर आते हैं। यहां एक रोचक बात यह है कि इंद्रधनुष के बाकी प्रायमरी कलर्स के पिगमेंट तो फैदर्स में होते हैं लेकिन नीले रंग का कोई पिगमेंट नहीं होता। तो फिर ‘नीलकंठ’ जैसे पंछी

के पंखों का रंग कहां से आता है? इसके पीछे भी विज्ञान काम करता है। नीले रंग के मामले में प्रकृति द्वारा बनाई पंख की संरचना मुख्य काम करती है। नीले रंग के पंखों का आकार और संरचना इस तरह की होती है कि जब प्रकाश इस पर पड़ता है तब यह पंख केवल नीले रंग को ही हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट या परावर्तित करता है। यहां यह भी याद रखना कि साधारण प्रकाश में इंद्रधनुष के सारे रंग छुपे होते हैं लेकिन नीले पंखों की डिजाइन ऐसी होती है कि वो हमारी आंखों तक केवल नीला रंग ही पहुंचाता है।



बचाओ पंख और पक्षी भी

ये जाहिर सी बात है कि पंख किसी पक्षी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और खूबसूरत पंखों के लिए पंछियों को मार देते हैं। दुनियाभर में इसके लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं ताकि निंदोष पक्षियों को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। हां, अगर जमीन पर गिरे पंख इकट्ठे करके कोई अपने पास रखे तो कोई बात नहीं।



रोचक बातें पंखों की

पंख पंछियों के नाजुक शरीर की रक्षा का काम करते हैं। कुछ पंछी तो ऐसे भी हैं जिनके नन्हे पंख उनके लिए आइलेंजेशन का भी काम करते हैं। उल्टू जैसे कुछ पक्षियों के पंख उनके लिए प्रोटेक्टिव शॉल का भी काम करते हैं और दुश्मनों की नजर से उन्हें पूरी तरह छुपा देते हैं। बर्फ में रहने वाले पंछियों के पैरों में भी पंख होते हैं और वे उनके लिए स्नो शूज का काम करते हैं। ये टंड के साथ-साथ उन्हें बर्फ में गिरा बनाए रखने में भी मदद करते हैं। कुछ पक्षी अपने पंखों से आवाज भी करते हैं। ये आवाज पंखों से गुजरने वाली हवा के कारण पैदा होती है।



टंड का समय था दिल्ली में बहुत ही ज्यादा टंड पड़ी थी। उस समय बादशाह अकबर और बीरबल दोनों ही सुबह-सुबह बगीचे में घूम कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल देख रहे हो कितनी ज्यादा टंड है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बिना गर्म कपड़ों के बाहर आ जाए तो वह तुरंत ही बर्फ की तरह जम जाएगा। जी हां जहांपना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीरबल ने अकबर से कहा।

अच्छा बीरबल यह बताओ इतनी टंड में भी तुम यहां आ गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इतनी सर्दी में घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे और अपने कामकाज को भी नहीं कर रहे होंगे। जी हां, जहाँपनाह आपकी बात तो सही है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो मजबूरी के चलते इस सर्दी में भी निकला करते हैं। मजबूरी में ऐसे काम किया करते हैं जो इस सर्द में नहीं करने चाहिए। बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल से कहा, अच्छा लेकिन मैं यह नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि कोई इतनी सर्दी में अपने घर से निकलेगा और काम पर जाएगा। वह तो घर के अंदर रहकर गर्म बिस्तर पर लेटा रहेगा। लेकिन उठकर काम पर नहीं जाएगा। नहीं नहीं जहाँपनाह बात ऐसी नहीं है। लोगों की मजबूरी है कि वह इस सर्द में भी निकल करकाम करें बीरबल ने अकबर को बताया। अच्छा! ऐसी बात है तो मुझे साबित करके दिखाओ कि कोई इतनी सर्दी में भी चंद पैसों के लिए भी काम करने को कैसे निकल सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल चुनौती देते हुए कहा। वही पास एक तालाब भी था जिसका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। बादशाह अकबर ने उस तालाब की ओर इशारा किया और बीरबल से कहा, बीरबल उस तालाब को देखो उस तालाब को देखकर ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका पानी कितना ठंडा होगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो रातभर इस तालाब में रहकर गुजार दें। मैं उसे ढेरों इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, आपका हुकुम सर आंखों पर। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा तुरंत करता हूँ और आज ही एक ऐसे व्यक्ति का इंतजाम करता हूँ जो यह कार्य कर देगा।

बीरबल तुरंत ही दरबार से निकला और इस बात का ऐलान कर दिया कि राजा उस व्यक्ति को ढेरों इनाम देंगे जो रात भर बगीचे की तालाब में रहकर गुजार देगा। जनता में से एक आदमी गंगाराम बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा, बादशाह सलामत रहे। मेरे बादशाह आपने जो करने को कहा था वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ। आज के लिए तुम हमारे मेहमान हो। जाओ और रात को हम तुम्हें उस तालाब में लेकर जाएंगे। उस तालाब पर तुम्हें पूरी रात गुजारनी है। रात का समय हुआ। गंगाराम को तालाब के पास ले जाया गया। गंगाराम ने तालाब का पानी छूकर देखा। तालाब का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था फिर भी गंगाराम हिम्मत करके तालाब के अंदर चला गया। शुरुआत में गंगाराम बहुत ही कांप रहा था लेकिन कुछ देर बाद वह सीधा खड़ा होकर पूरा रात गुजार दिया। दिन होते ही उसे बादशाह के दरबार पर बुलाया गया। बादशाह अकबर उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत ही गंगाराम से पूछा, आखिरकार तुम पूरी रात इतनी ठंडी में कैसे रह गए? अगर मैं होता तो मैं मर ही जाता।

गंगाराम ने बादशाह अकबर के सवालों को जवाब दिया, जहांपना, पास ही मैं एक जलता हुआ दीपक था जिसकी ओर ध्यान कर उसे देखकर मैं पूरी रात गुजार गया। मैंने अपना पूरा ध्यान उसपर रखा। ओह! तो यह बात है। तुमने उस दीपक से गर्मी ली और उस गर्मी से पूरी रात भर तालाब में रह गए। तो तुमने

बीरबल की खिचड़ी

तो हम सब के साथ धोखा किया है। वैसे मैं तुम्हें जाने देता हूँ, क्योंकि यह काम करना आसान नहीं था। लेकिन तुमने जिस तरीके का काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगा। यह कहकर बादशाह ने गंगाराम को वापस भेज दिया। वही पास में बीरबल खड़ा यह सब चीजें देख रहा था। तभी राजा ने बीरबल से कहा, देखा बीरबल इस तरह का काम कोई भी नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहाँपनाह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह कहकर बीरबल अपने घर लौट गया। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को खाने में आमंत्रित किया। बीरबल ने कहा, बादशाह मैं बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल आप मेरे घर आए और मेरी हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाए। राजा ने बीरबल का निमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन बीरबल के घर जा पहुंचे। बीरबल के घर पहुंचते ही बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, लेकर आओ तुम्हारी खिचड़ी जरा हम भी तो उसका स्वाद ले कर देखें कि आखिर तुम कैसी खिचड़ी बनाते हो? जी हां जहाँपना बस खिचड़ी तैयार होने वाली है। बीरबल ने कहा। ठीक है राजा ने कहा। समय बीतता जा रहा था और राजा का भूख बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में बादशाह ने बीरबल से फिर पूछा, बीरबल तुम्हारी खिचड़ी बनने में और कितना समय लगाया। मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। बीरबल ने जवाब दिया, बस जहाँपना कुछ देर और आप की खिचड़ी तुरंत तैयार हो जाएगी। अच्छा ठीक है। जल्दी लेकर आओ। ऐसे करते करते और समय बीत गया और राजा का भूख बढ़ने लगा था उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा खिचड़ी तैयार नहीं हुआ। जल्दी लेकर आओ मुझे बहुत भूख लगी है

जी हां जहाँपनाह मैं अभी लेकर आता हूँ, बस यह तैयार होने वाला है। यह कहकर बिरबल फिर अपनी रसोई की ओर चला गया। कुछ समय और बीतने के बाद राजा उठकर बीरबल की रसोई की ओर जा पहुंचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हांडी(पकाने का बरतन) को आग से बहुत ही ऊपर लगाकर रखा था। जिससे कि आग की ताप उस हांडी तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में राजा ने बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ! तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसे में तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी। पकेगी जहाँपनाह यह जरूर पकेगी। बीरबल ने कहा। अरे आग का ताप तो हांडी में पहुंच ही नहीं रहा है तो फिर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है। इसके लिए आग का ताप खिचड़ी की हांडी तक पहुंचाना चाहिए। राजा ने समझाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक गंगाराम को ताप दे सकता है। तो इस तरह से हांडी को आग से ताप अवश्य ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुरंत ही राजा ने बीरबल को कहा, बीरबल मैं समझ चुका हूँ कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं तुरंत ही गंगाराम को बुलाकर उसका इनाम उसे दूंगा और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी गलती को मुझे बताया।



पीएम मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी का करेंगे दौरा



लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के लिए भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री रविवार (25 अक्टूबर) को वाराणसी में होने वाले पहले एयर फ़ोर्स एयर शो में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। भाजपा ने शहर और जिले भर में 13 स्वागत स्थल तय किए हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग ढोल-नगाड़ों, शंख ध्वनि, डमरू वादन और फूलों की वर्षा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके अलावा, भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले संगीत और नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे। एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए शहर को 32 ज़ोन, 50 सेक्टर और 80 उप-सेक्टर में बांटा है।

राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भाजपा का तीखा तंज



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को राहुल गांधी के बार-बार विदेश दौरे करने को लेकर उन पर फिर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) लगातार भारत की छवि खराब कर रहे हैं और देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। भाजपा ने कहा कि बार-बार चुनाव हारने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बार-बार री-लॉन्च कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी अपने विदेश दौरों के दौरान संदिग्ध लोगों से मिलते हैं, जिसे उन्होंने राष्ट्र-विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न केवल भाजपा और हिंदू धर्म पर हमला कर रही है, बल्कि राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए भारत की संस्थाओं को भी निशाना बना रही है। राहुल गांधी की हालिया वियतनाम यात्रा का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मूल विचारधारा भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी नफरत रखना है।

राजभर की चुनौती, सपा मुस्लिम सीएम का चेहरा घोषित करे



लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 23 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक सीधे राजनीतिक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव सच में मुस्लिम समुदाय की भलाई चाहते हैं, तो उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। अंबेडकर नगर में बोलेते हुए, राजभर ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए प्रशासनिक दबाव के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप असल में हार के डर से बनाए गए बहाने हैं। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में जेल में आजम खान से मुलाकात करने पर भी निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश को आजम खान की याद तब आई जब चुनाव आ गए। इतने सालों तक उन्हें कभी आजम खान का खयाल नहीं आया।

सुखबीर बादल ने दिए भाजपा के साथ गठबंधन के संकेत



चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में फिर से शामिल हो सकती है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्हें राज्य में अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बताया। भाजपा का नाम लिए बिना, बादल ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब की बेहतरी के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस-आप छोड़ किसी से भी गठबंधन को तैयार है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा, अकाली दल की सरकार में यहां शांति थी।

रेहान वाद्रा की फोटो प्रदर्शनी पर राजीव चंद्रशेखर ने उठाया सवाल

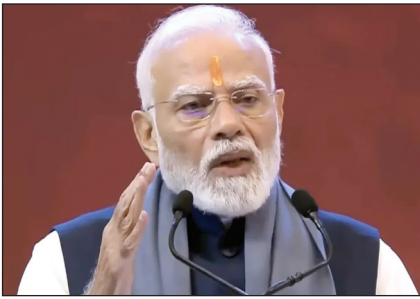
तिरुवनंतपुरम। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरलम इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के बेटे रेहान वाद्रा की 'फोटो प्रदर्शनी' आयोजित करने की मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन की पेशकश पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि रेहान को “विशेष तरजीह” दी जा रही है। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री ने यह पेशकश ऐसे समय में की है, जब राज्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री के किसी भी प्रदर्शनी को केरलम में आयोजित करने का निमंत्रण देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वह वायनाड की सांसद (प्रियंका गांधी) के बेटे की हो क्यों न हो, लेकिन गलत यह है कि इस युवक को विशेष तरजीह दी जा रही है, जबकि केरलम के अन्य युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन पर आंसू गैस के गोले दागती है और उनके साथ मारपीट करती है।” भाजपा नेता ने राहुल गांधी और सतीशन सहित कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या लोकतंत्र और अधिकार केवल एक राजनीतिक परिवार के सदस्यों के लिए ही मायने रखते हैं।

प्रधानमंत्री ने चिन्मय अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन, कहा-

चिन्मय मिशन सिर्फ एक संस्था नहीं, ये चिन्मय विचार हैं : मोदी

नई दिल्ली। 23 अक्टूबर को नई दिल्ली में चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत उन्नति को राष्ट्रीय प्रगति का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इस आध्यात्मिक गुरु ने आध्यात्मिक विकास को राष्ट्र के विकास से जोड़ने का प्रयास किया। भारत मंडपम में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक वैदिक मंत्र, वयं राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता: का उल्लेख किया। यह मंत्र नागरिकों का आह्वान करता है कि वे राष्ट्र को जागरूक और उन्नत बनाने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का भला चाहने वाले लोगों के रूप में, हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र को जागरूक और उन्नत बनाएं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपना पूरा जीवन इसी मंत्र से प्रेरित होकर जिया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को लोगों के अस्तित्व का आधार बताया और स्वामी चिन्मयानंद के उस विचार को याद किया, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति को व्यक्तिगत उन्नति और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में अपने देश के प्रति आत्म-सम्मान की भावना जगाना स्वामी जी का मिशन था। इसी उद्देश्य से उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की और उपनिषदों, वेदांत तथा हमारे धर्मग्रंथों के ज्ञान को



आम लोगों तक पहुँचाया। आज हम उनके उस संकल्प का परिणाम देख सकते हैं।

चिन्मय मिशन के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे केवल एक संस्था से कहीं बढ़कर बताया। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक संत की दूरदृष्टि से उपजा चिन्मय विचार कहा। उन्होंने कहा कि आप सभी की शुभकामनाओं से, आज मुझे चिन्मय मिशन के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। यह एक बिल्कुल अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। यह मेरे प्रति हमारे संतों का विशेष स्नेह और आशीर्वाद है।

उन्होंने आगे कहा कि चूँकि चिन्मय मिशन केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक ‘चिन्मय विचार’ है, जिसकी नींव एक ‘चिन्मय ऋषि’ ने रखी थी। दशकों की इसकी यात्रा भी ‘चिन्मय संकल्पों’ से भरी रही है। और जो कुछ भी ‘चिन्मय’ है, वह स्वाभाविक रूप से अमर है, वह अमृतमय है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत जब अपनी आजादी के 100

साल पूरे करेगा, उसी कालखंड में चिन्मय मिशन भी अपनी शताब्दी का वर्ष मनाएगा यानी चिन्मय मिशन की शताब्दी यात्रा और विकसित भारत की यात्रा एक साथ आगे बढ़ेगी। इसलिए हमारे लक्ष्य भी एक हैं, उद्देश्य भी एक है और हमें इस यात्रा को एकसाथ आगे बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को एक बेहद निजी और आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक ने उन्हें स्वामी चिन्मयायंद के साथ बिनाए पलों की याद दिला दी है। यह कार्यक्रम चिन्मय मिशन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिसकी स्थापना 1951 में इसी आध्यात्मिक गुरु ने की थी।

मोदी ने कहा कि बीते दशकों में समय बदला है, देश के सामने नई चुनौतियाँ पैदा हुई हैं, समाज में नई विकृतियाँ आई हैं। आज उनके समाधान का दायित्व हम सबके ऊपर है। आज हमें बांटने वाली ताकतों के खिलाफ समाज को एकजुट करना है। हमें आत्मनिर्भरता के लिए देशवासियों को जागरूक करना है। 2047 में विकसित भारत के संकल्प से जन-जन को जोड़ना है। इन उद्देश्यों के लिए हमें और सक्रिय होना है। चिन्मय मिशन के प्रयास से आज लाखों युवा हैं... जो भारत के सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसेडर का काम कर रहे हैं। ये भारतीय युवा पत्रिका को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तभी होगा, जब सपा कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देगी। जहां झुकना होगा हम झुकेंगे भी लेकिन हमें अब 2024 से आगे बढ़ना है क्योंकि तब से अब तक उत्तर प्रदेश और कांग्रेस में बहुत कुछ बदल चुका है। गांव-गांव में कांग्रेस खड़ी हो गई है। गठबंधन तभी सफल होतों है जब नेताओं के साथ-साथ नीचे जमीन पर कार्यकर्ताओं और जनाधार में भी तालमेल और समन्वय हो। इसके लिए एक-दूसरे का सम्मान और हिस्सेदारी जरूरी है। यह कहना है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने।

गौतम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझे राहुल जी ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम दिया है। मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि यहां – फसल लहलहाएगी और कांग्रेस – फिर से खड़ी होगी। कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के अहम – हिस्से हैं और हमारा समान उद्देश्य है, भाजपा को सत्ता से हटाना। इसलिए दोनों दलों ने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव – मिलकर ही लड़ेंगे। दलों के नेताओं- के बयानों पर गौतम कहते हैं कि- कोई तल्खी नहीं है दलों के बीच बयानबाजी होती रहती है। आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने लड़ा। आज – जो भारत देख रहे हैं उसके पीछे – कांग्रेस के नेताओं की ही सोच है। मैंने यही कहा कि सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी होने के नाते हमें बाबर का सम्मान चाहिए। हम उनको भी – सम्मान देंगे जो हमें सम्मान दें।



गठबंधन में सीटों के बंटवारे का आधार 2022 के चुनाव होंगे या 2024 के चुनाव इस सवाल के जवाब में गौतम कहते हैं कि किसी भी पार्टी में उतार-चढ़ाव आते हैं। यूपी में हम अर्श से फर्श पर आ गए थे, लेकिन भारत जोड़ी यात्रा के बाद राहुल गांधी ने एक नई कांग्रेस बनाई है। जनता के मुद्दों पर सड़क से संसद तक

लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं। उससे लोगों में राहुल गांधी के प्रति भरोसा पैदा हुआ है। उस भरोसे ने लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा राजस्थान में अच्छे नतीजे दिए।

यह भरोसा अकेले समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बना, बल्कि राहुल गांधी के प्रति जो भरोसा बना उससे इंडिया ब्लॉक के प्रति भरोसा बढ़ा और अच्छा रिजल्ट आया। कोई कहता है कि आप 2024 से पहले कहीं नहीं थे तो फिर मेरा कहना है कि अब से चालीस साल पहले हम ही थे।

अगर सरकार बनती है तो क्या कांग्रेस अपना उपमुख्यमंत्री चाहेगी इसके जवाब में गौतम कहते हैं कि इसकी संभावना है लेकिन सारी बातें चुनाव के बाद तय होंगी। हमारा पहले लक्ष्य भाजपा को सत्ता से हटाना है। गठबंधन में कुछ और छोटे दलों को शामिल करने के सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जरूर आना चाहिए। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। औवैसी को साथ लेने के सवाल पर गौतम कहते हैं कि भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ही कर सकती है।

खरगो ने मोदी सरकार से पूछे तीन सवाल

चीन को कितनी बार क्लीन चिट देंगे?

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगो ने केंद्र सरकार की सीमा और विदेश नीति पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजिंग को पहले ही काफी क्लीन चिट दी जा चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री को भारत के सामने सच साफ-साफ रखना चाहिए। एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और राजनयिक जवाबदेही से जुड़े तीन अहम सवाल पूछे हैं। सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए, खरगो ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक की उन टिप्पणियों का जिक्र किया, जो अरुणाचल प्रदेश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ हुई झड़पों से जुड़ी थीं।

खरगो ने केंद्र सरकार से सवाल किया, अरुणाचल प्रदेश में पीएलए के साथ लगातार हो रहे टकराव की आईटीबीपी डीजी की ओर से पुष्टि बेहद चिंताजनक है। डोकलाम और गलवान के बाद, क्या कोई और गंभीर टकराव शुरू हो रहा है? अगरस्त में तकिंगम के पास चीनी घुसपैट की खबरें सामने आई थीं। फिर भी, वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिव बाद



भी – जो कि कथित तौर पर यहां से सिर्फ 180 किमी दूर है – टकराव जारी है। क्या भारत की पेट्रोलिंग (गश्त) करने की पहुंच प्रभावित हुई है? उन्होंने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और पूछा कि देश को इस बारे में अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है।

राजनयिक मुलाकातों पर सवाल उठाते हुए, खरगो ने पूछा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच हुई कई द्विपक्षीय वार्ताओं का ज़मीनी स्तर पर क्या नतीजा निकला है। खरगो ने पूछा, मोदी और शी के बीच कम से कम 23 मुलाकातों और बातचीत हुई, एनएसए अजीत डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों के 25 दौर की वार्ताएं हुईं, डब्ल्यूएमसीसी की 36 बैठकें हुईं, और लगातार एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुए। इन मुलाकातों से क्या ठोस परिणाम निकले? क्या मई 2020 से पहले भारत को हासिल गश्त (पेट्रोलिंग) करने के अधिकार पूरी तरह बहाल हो गए हैं?

स्टेल प्रमुख समाचार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज

क्राइस्टचर्च। भारत पहले मैच में बल्लेबाजों के



दम पर बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा लेकिन अगर उसे अपना विजय अभियान जारी रखना है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उसके गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पिछले कुछ समय की तरह इस मैच में भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन साधारण रहा। अगर बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो परिणाम उल्टा हो सकता था। भारत ने 226 रन का रिकार्ड लक्ष्य हासिल करके पांच मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली लेकिन बल्लेबाजों पर अत्यधिक निर्भरता बाकी मैचों में भारी पड़ सकती है।

भारत के लिए पांचवें और छठे गेंदबाज का विकल्प चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि चोटिल हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में अन्य ऑलराउंडर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। पहले मैच में नीतीश रेड्डी ने चार ओवर में 40 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला जबकि नमन धीर को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी में मैच विजेता पारी खेली। भारत की गेंदबाजी की मुश्किलों को और बढ़ाने वाली बात यह है कि श्रृंखला के पहले मैच में उसके प्रमुख गेंदबाजों की जमकर थुनाई हुई। लगभग चार साल बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रहे भुवनेश्वर कुमार अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे और उन्होंने चार ओवरों में 49 रन लुटा दिए। उनका दो नो-बॉल और उतनी ही वाइड गेंदों से पता चलता है कि उन्हें लय में आने के लिए और समय चाहिए। फिन एलन और उनके साथी सलामी बल्लेबाज टिम सोफ्ट ने पावरप्ले में भुवनेश्वर और अर्शदीप पर मनचाहे चौके लगाकर इन दोनों तेज गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। दूसरे मैच में भी बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने की उम्मीद है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/प्रमुख समाचार

उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 126 अंक टूटा, निफ्टी 22600 पर बंद

नई दिल्ली। मजबूत शुरुआत के बाद शुक्रवार दोपहर के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार में अचानक भारी बिकवाली हावी हो गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट करूड की कीमतें 114 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गईं, जिससे निवेशकों की भावना काफी प्रभावित हुई। इसके साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से लगातार जारी बिकवाली ने घरेलू बाजार के दबाव को और बढ़ा दिया, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मुख्य सूचकांक लगभग 1 प्रतिशत तक टूट गए। हालांकि कारोबार के अंत में रिकवर करते हुए सेंसेक्स 125.56 अंक घटकर 73,123.83 और निफ्टी 87.66 अंक गिरकर 22,600 पर बंद हुआ। शुक्रवार को रुपया लगातार दूसरे दिन गिरकर 94.93 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ।

जियो आईपीओ ने 1 करोड़ आवेदन के साथ बनाया रिकॉर्ड

मुंबई। देश के सबसे बड़े जियो आईपीओ ने एक और इतिहास रच दिया है। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार किसी आईपीओ में आवेदनों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जियो प्लेटफॉर्मस के 30,213 करोड़ रुपए के आईपीओ ने यह रिकॉर्ड शुक्रवार को तीसरे और अंतिम दिन बनाया। शुक्रवार 12 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, आईपीओ में अब तक 1,00,15,118 आवेदन आ चुके हैं। निवेशकों के जबरदस्त उत्साह के बीच आईपीओ कुल 6.89 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बड़े संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी 14.38 गुना भर गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा आवेदन पाने का रिकॉर्ड Waaree Energies के नाम था। अक्टूबर 2024 में उसके आईपीओ को 97.34 लाख आवेदन मिले थे।

सरकारी कंपनियों की बिक्री को फिर मिलेगी रफ्तार? विनिवेश नीति के सामने बड़ी चुनौतियां

ए के भट्टाचार्य

नरेंद्र मोदी सरकार तेजी से विनिवेश करती दिख रही है। यह सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की रणनीतिक बिक्री के लिए 2021 में घोषित उसकी नीति धीरे-धीरे और रुक-रुककर अमल में आने के बाद हो रहा है। गत सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की कुल हिस्सेदारी के 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से को उस कीमत पर बेचने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया, जिससे सरकार को चालू वित्त वर्ष में 26,500 करोड़ रुपये की विनिवेश आय होनी चाहिए।

वित्त वर्ष 2026-27 समाप्त होने में 5 महीने से अधिक समय बचा है और सरकार परिसंपत्तियों की ऐसी बिक्री से 80,000 करोड़ रुपये के सालाना लक्ष्य से अधिक राशि जुटा चुकी होगी। आईडीबीआई बैंक सौदे का एक अर्थ यह भी है कि मोदी सरकार कुछ

ठहरने के बाद एक बार फिर निजीकरण पर जोर दे रही है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कोई इकलौता मामला नहीं है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार की योजना तीन और सरकारी उपक्रमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की है। ये कंपनियां इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फांडेस लिमिटेड (आईआईएफसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईईएल) हैं।

एमसीएल और एसईसीएल को सूचीबद्ध करने से शायद सरकार को बिल्कुल भी विनिवेश आय नहीं होगी क्योंकि ये दोनों कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई हैं। ऐसे में इनकी हिस्सेदारी बिकने से मिली पूरी रकम कोल इंडिया के



पास ही जाएगी। लेकिन आईआईएफसीएल पूरी तरह सरकार की कंपनी है और अगर उसे मार्च 2027 के पहले सूचीबद्ध कर दिया गया तो विनिवेश से और अधिक आय होगी। इसका आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं।

निजीकरण के मामले में सरकार का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसने 2021 में बनी रणनीतिक विनिवेश की नीति में कुछ गिने-चुने महत्वपूर्ण पीएसयू को छोड़कर सभी सरकारी उपक्रमों से बाहर निकलने का फैसला किया था। लेकिन नीति बनने के बाद से अभी तक एयर इंडिया, फेरो

स्क्रैप निगम, नीलाचल इस्पात निगम और इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कोरपोरेशन का ही निजीकरण हो पाया है। एयर इंडिया भारीभरकम और नामी कंपनी थी मगर भारी कर्ज में फंसी थी, इसलिए जनवरी 2022 में उसके निजीकरण से सरकार को 2,700 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति ही हुई।

अन्य तीन कंपनियों की बिक्री से भी सरकार को ज्यादा रकम नहीं मिली। फेरो स्क्रैप निगम और नीलाचल इस्पात निगम के निजीकरण से कोई आय नहीं हुई और इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कोरपोरेशन बेचने से 118.73 करोड़ रुपये ही मिले। इस तरह चार कंपनियों के निजीकरण से सरकार को कुल 2,818.73 करोड़ रुपये ही मिले। सरकार की विनिवेश नीति के आलोचकों ने अभी तक इस आंकड़े को मुद्दा नहीं बनाया है, लेकिन जब वे ऐसा करेंगे तो सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री की नीति पर सवाल और भी गहरे हो जाएंगे। मोदी सरकार के पिछले साढ़े

बारह वर्षों में विनिवेश से कुल 4.37 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है। किंतु इसमें निजीकरण से प्राप्त रकम का हिस्सा केवल 0.64 प्रतिशत यानी बेहद मामूली है। शेष राशि अल्पांश हिस्सेदारी वाले शेयरों की बिक्री से जुटाई गई है। पिछले डेढ़ वर्ष में परिसंपत्तियों के मुदीकरण (यानी सरकारी जमीन तथा इमारत बेचे जाने) में तेजी आई है। इससे लगभग 34,787 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। लेकिन परिसंपत्ति मुदीकरण से मिली रकम जोड़ लें तब भी मोदी सरकार का कार्यकाल में अब तक विनिवेश से हुई कुल आय इस दौरान सार्वजनिक उपक्रमों से मिले लगभग 5.32 लाख करोड़ रुपये के लाभांश से कम रही है। शायद यह भी एक वजह रही कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से अपने विनिवेश कार्यक्रम की गति धीमी कर दी। विडंबना यह है कि सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री की नीति भी सरकार उसी वर्ष लाई थी।

रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर से बदलेगी जशपुर की तस्वीर, राजधानी रायपुर तक का सफर होगा आसान

मुख्यमंत्री साय के प्रयासों से जशपुर में आकार ले रही 3147 करोड़ की भारतमाला परियोजना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों से जशपुर जिले में सड़क अधोसंरचना के विकास को नई गति मिल रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण जशपुर जिले में आकार लेने लगा है। जिले में लगभग 3147 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही इस सड़क परियोजना के पूर्ण होने से जशपुर का राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों और पड़ोसी राज्यों से सड़क संपर्क अधिक सुगम होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से जिले में व्यापार, पर्यटन, कृषि आधारित गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

निर्माणधीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 707 किलोमीटर बताई गई है, जिसमें लगभग 104 किलोमीटर सड़क जशपुर जिले से होकर गुजरेगी। यह फोरलेन सड़क रायपुर और धनबाद के बीच आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ जशपुर, पथलगांव और आसपास के क्षेत्रों को



व्यापक सड़क नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्रदेश की राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, ऊर्जाधानी कोरबा और पड़ोसी राज्य झारखंड की ओर आवागमन की सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित हो रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर से जशपुर जिले के लोगों को सबसे बड़ा लाभ यात्रा समय में कमी के रूप में मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में जशपुर से राजधानी रायपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में लंबा समय लगता है। परियोजना के पूर्ण होने पर बेहतर फोरलेन सड़क और सुगम यातायात

व्यवस्था से यात्रा अवधि में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। उपलब्ध परियोजना संबंधी जानकारी के अनुसार, संबंधित मार्गों पर यात्रा अवधि लगभग 14 घंटे से घटकर 8 से 9 घंटे होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं जशपुर से रायपुर तक का सफर भविष्य में लगभग 5 से 6 घंटे में पूरा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक यात्रा अवधि मार्ग की उपलब्धता, यातायात की स्थिति और परियोजना के पूर्ण संचालन पर निर्भर करेगी। सड़क संपर्क बेहतर होने से जिले के नागरिकों को राजधानी रायपुर और अन्य बड़े शहरों में स्वास्थ्य

सेवाओं, उच्च शिक्षा, व्यापार और प्रशासनिक कार्यों के लिए आने-जाने में सहूलियत होगी। रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जशपुर जिले की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित होने से किसानों को अपनी कृषि उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से उद्यानिकी फसलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के परिवहन में लगने वाला समय कम होने से किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है। जशपुर जिला कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प और ग्रामीण आजीविका गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। आधुनिक सड़क संपर्क से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार और नए उद्यमों के विकास के अवसर बढ़ सकते हैं। सड़क निर्माण और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बल मिलेगा।

एनसीबी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने 11 मेडिकल स्टोर्स का किया निरीक्षण

चार मेडिकल स्टोर्स में अभिलेखों के संधारण में अनियमितता मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी

रायपुर। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रायपुर की संयुक्त टीम ने आज जिले के 11 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग की आशंका वाली औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय, अनधिकृत भंडारण और वितरण पर नियंत्रण के साथ औषधि संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना था।

निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स में औषधियों के क्रय-विक्रय, उपलब्ध स्टॉक, भंडारण व्यवस्था और संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। टीम ने यह भी देखा कि औषधियों की खरीदी अधिकृत स्रोतों से हो रही है या नहीं तथा क्रय-विक्रय और स्टॉक कार्डों निर्धारित नियमों के अनुरूप रखा जा रहा है या नहीं। जांच में सर मेडिकल्स,



भनपुरी; श्री राम मेडिकल स्टोर्स, कोटा; लक्ष्मी मेडिकल शॉप, संतोषी नगर; और मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, कुकुरबेड़ा में औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों के संधारण में अनियमितताएं पाई गईं। संबंधित चारों फर्मों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। फर्मों से प्राप्त जवाब और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त निरीक्षण दल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से निरीक्षण एवं निगरानी जारी रहेगी।

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती हंसा साहू और श्री ओम प्रकाश यादव शामिल थे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार अधिकारी भी दल में मौजूद रहे।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की है कि वे केवल वैध स्रोतों से औषधियों का क्रय करें, स्टॉक और क्रय-विक्रय के अभिलेख अद्यतन रखें तथा लाइसेंस की शर्तों सहित लागू नियमों का कड़ाई से पालन करें। औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए विभागीय समन्वय से निरीक्षण एवं निगरानी जारी रहेगी।

मैनपाट टाइटन्स-बैलाडिला बुल्स के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का दूसरा दिन : प्रहलाद बने स्ट्राइकर ऑफ़ द मैच, करण धनुक को प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार



मैच चुना गया, जबकि करण धनुक को प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला।

मैच का पहला हमला चौथे मिनट में देखने को मिला। मैनपाट के खिलाड़ियों ने सर्कल में प्रवेश तो किया, लेकिन विपक्षी डिफेंडरों ने आसानी से गेंद को बाहर निकाल दिया। इसके बाद जवाबी हमले में बैलाडिला बुल्स

ने भी सर्कल में जगह बनाई, लेकिन उनके पास डिफेंस को चुनौती देने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। मैच के 7वें मिनट में मैनपाट के पास गोल करने का एक बेहतरीन मौका आया, जब प्रहलाद टांडी को सर्कल के अंदर गेंद मिली, लेकिन बैलाडिला बुल्स के गोलकीपर ने तेजी से आगे आकर इस मौके को नाकाम

कर दिया। लगातार हमलों के बीच बैलाडिला को अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे संदीप ठाकुर ने गोल में बदल दिया। यादव अपनी बाईं ओर नहीं जा सके, जबकि गेंद उनके काफी करीब थी। बहरहाल, पहला क्वार्टर बिना किसी और हलचल के समाप्त हुआ। दूसरे क्वार्टर में मैनपाट ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया। हालांकि ज्यादा मौके नहीं बने थे, लेकिन हाफ-टाइम से कुछ मिनट पहले प्रवीण यादव ने गोल कर दिया। प्रहलाद ने सर्कल के अंदर शानदार दौड़ लगाई और प्रवीण ने गेंद को बेहतरीन तरीके से डिफ्लेक्ट करके गोल में बदल दिया। हाफ-टाइम तक स्कोर 2-0 हो गया था।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ प्रवास के पश्चात रायपुर से हुई रवाना

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के समापन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर से रवाना हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेश डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रपति को आत्मीय विदाई दी। विमानतल पर मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

जिले की 22 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव की तैयारी जारी

गरियाबंद। पंचायत उपचुनाव 2026 के तहत गरियाबंद जिले की 22 ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। जारी सूची के अनुसार, जिले में कुल 22 पद रिक्त हैं, जिनमें 21 पंच पद और एक सरपंच पद शामिल है। रिक्त पदों वाली ग्राम पंचायतों में गरियाबंद विकासखंड की हरदी, पोतिया, छिंदौला, मरदाकला और धवलपुरडीह शामिल हैं। छुरा विकासखंड की करकरा, कुरूद, खरखरा और बोडराबांधा-ब, फिंगेश्वर विकासखंड की कुह्नी, बरभाठा और अरण, मैनपुर विकासखंड की सगड़ा, काण्डेकेला, तोरिंगा, मैनपुरखुर्द, कुल्हाड़ीघाट, जांगड़ा और सरईपानी तथा देवभोग विकासखंड की कुहीमाल, कुम्हड़ईकला और कोसमकानी ग्राम पंचायतों में भी रिक्त पद हैं। इन 22 ग्राम पंचायतों में कुहीमाल ग्राम पंचायत में सरपंच का एक पद रिक्त है, जबकि शेष 21 ग्राम पंचायतों में पंच के पद रिक्त हैं।

निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया। मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां 30 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 3 नवंबर तक किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

टीईटी की परीक्षा ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन कराए सरकार : कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को ऑनलाइन कराने के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित किया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार को प्रदेश के लगभग 50 हजार शिक्षकों की उम्र, अनुभव और व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली निर्धारित करनी चाहिए। विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे शिक्षकों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा अनावश्यक मानसिक दबाव और परेशानी का कारण बन सकती है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन बच्चों का भविष्य संवारने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में लगाया है। आज जब उनके अनुभव और सेवाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, तब उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा की प्रक्रिया में उलझना उचित नहीं है। हर शिक्षक से कंप्यूटर संचालन में समान दक्षता की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। शिक्षकों के ज्ञान, अनुभव और शिक्षण क्षमता का आकलन होना चाहिए, न कि उनकी कंप्यूटर चलाने की दक्षता का। सरकार को यह समझना चाहिए कि परीक्षा का उद्देश्य शिक्षकों की योग्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है, न कि उन्हें तकनीकी असुविधाओं के कारण परेशान करना।

धान खरीदी की तैयारियां 10 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश



कवर्धा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्पण मूल्य पर धान खरीदी को सुचारु, पाददर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कबीरधाम जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य विभाग ने नवीन धान उपार्जन समितियों एवं केंद्रों के प्रबंधकों और प्रभारियों की बैठक आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं 10 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन की धान खरीदी संबंधी गाइडलाइन का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कुल 145 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें 108 पूर्व से संचालित तथा 37 नवीन उपार्जन केंद्र शामिल हैं। खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी केंद्रों में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बैठक में खाद्य अधिकारी ने समिति प्रबंधकों एवं केंद्र प्रभारियों से धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियों की बिंदुवार जानकारी ली।

प्रदेश में संगठित आयुष्मान घोटाला हो रहा : कांग्रेस

रायपुर। फर्जी मरीजों के आयुष्मान योजना के तहत इलाज बताकर लोकधन की लूट के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को बराबर का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार में गरीबों की बीमारी भी कमाई का साधन बन चुकी है। आयुष्मान भारत योजना में फर्जी मरीज दिखाकर करोड़ों रुपये की कमीशनखोरी और घोटाला अंजाम दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों से तक फर्जी मरीज लाने की शिकायतें आई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में यह डाका पड़ा है, वही विभाग इसकी जांच का ढोंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग खुद आरोपों के कटघरे में है, आरोपी ही अगर जांचकर्ता बन जाए, तो न्याय कैसे मिलेगा? कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करती है कि हमें विभागीय लीपापोती पर बिल्कुल पुरोसा नहीं है। इस बहुचर्चित घोटाले की निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की सीधी निगरानी में कराई जाए। जब योजना में संध लगाने वाला खुद विभाग और उसके भ्रष्ट अधिकारी हों, अस्पताल प्रबंधन हों, तो विभाग द्वारा खुद कराई जा रही जांच केवल एक खातापूर्ति और लीपापोती है। स्वास्थ्य विभाग खुद संदेह के दायरे में है।

उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मान



दंतेवाड़ा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने तथा शैक्षणिक नवाचारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आचार्य विनोबा भावे शिक्षक सहायक कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस पहल के माध्यम से विद्यालयों में बेहतर शिक्षण पद्धतियों को अपनाने, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने और सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पहचान दी गई। कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर एवं जिला परियोजना समन्वयक हरीश गौतम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर उनके प्रयासों की सराहना की। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में सुनीता अजित, बलराम रेड्डी, शिवकुमार गुप्ता, कीर्तिता कोठारी, पुष्पा ध्रुव, नीता साहू और माधुरी उके शामिल रहे। इस अवसर पर विनोबा टोम के अभिषेक त्रिपाठी एवं राहुल भी उपस्थित रहे।

कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की संभागीय बैठक सम्पन्न

खरीफ 2026 की समीक्षा एवं रबी 2026-27 की कार्ययोजना पर हुई विस्तृत चर्चा

बिलासपुर। राज्य शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कृषि सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कृषि एवं संबद्ध विभागों की संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित कृषि गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी रबी वर्ष 2026-27 के कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती-किसानी के साथ कुकुटपालन, मछलीपालन, बकरीपालन और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर योजनओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।



बैठक में खरीफ सीजन के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा के साथ रबी सीजन की तैयारियों पर चर्चा किया गया। कृषि एवं संबद्ध विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने कहा कि खरीफ सीजन में बिलासपुर संभाग में अच्छा कार्य हुआ है, जिसमें सम्भाग के सभी जिलों

का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में भी इसी तरह हम सबको सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा, ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उन्होंने कृषि एवं संबद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचाने पर जोर दिया। रबी वर्ष 2026-27 की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को

आवश्यक कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के लिए किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ वैकल्पिक एवं लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बिलासपुर संभाग में कृषि विकास के व्यापक संभावना हैं, जिनका लाभ उठाते हुए दलहन, तिलहन, प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने बस्तर की विश्व प्रसिद्ध और पवित्र परंपरा 'बस्तर दशहरा' को प्रशासनिक तानाशाही का शिकार बना दिया है। जिस जोगी विधान के बिना बस्तर का दशहरा अधूरा माना जाता है, उस जोगी दौलत नाग और उनके परिवार को राष्ट्रपति जी के दौरे की सफाई का बहाना बनाकर सिरहासर भवन से बेदखल कर दिया गया। 3 दिन पहले पवित्र रथ को जेसीबी से खिंचवाकर धरोहर 'बस्तर दशहरा' पर वर्तमान भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा पहुंचाई गई ठेस अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और आक्रोश पैदा करने वाला विषय है। राष्ट्रपति



गया। यह बस्तर के आदिवासियों की आस्था पर सीधा हमला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर की पावन और सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर 'बस्तर दशहरा' पर वर्तमान भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा पहुंचाई गई ठेस अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और आक्रोश पैदा करने वाला विषय है। राष्ट्रपति

महोदया के दौरे और 'सफाई' के खोखले बहाने के नाम पर जोगी विधान निभाने वाले पारंपरिक सिरहा/जोगी (दौलत नाग एवं उनके परिवार) को दशहरा संपन्न होने से पहले सिरहासर भवन से जबरिया बेदखल करना सीधा-सीधा आदिवासी आस्था, परंपरा और बस्तरिया स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना है। 3 दिन पहले रथ को जेसीबी से खिंचवाना और अब पवित्र जोगी परिवार को नवाखाना, बाहर रैनी, काछन जात्रा, कुकुट्र बाज्रा और माँ दैतेश्वरी की बिदाई रस्मों से दूर रखना यह साबित करता है कि भाजपा के लिए बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा केवल 'इवेंट मैनेजमेंट' बनकर रह गया है।